

जय स्तार पर्यावरण समाधान निधि (एस.ई.आई.ए.ए.) फ्लोरिडा की 210वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण सभाबाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छल्लासंगठ की 230वी बैठक दिनांक 17/11/2025 को अपरान्ह 04:00 बजे श्री पोलिमेट्री बैकट मर्चिसंग राय, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण सभाबाट निर्धारण प्राधिकरण, छल्लासंगठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य एवं सदस्य सचिव उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समन्वय निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अभ्युक्ति एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। संयुक्तित एजेंडावार चर्चाकर विन्यासुसार निर्णय लिया गया।

एजेन्डा सायटम क्रमांक-१

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ (परिवेश 1.0) की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य तकनीकों/अन्य परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्याम कुमार प्रजापति त्रिवस्त (प्रो.— श्री श्याम कुमार प्रजापति), ग्राम—लोहरी, तहसील—लोहरी, जिला—मुंगेरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2367)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428210/2023, दिनांक: 18/04/2023 द्वारा भर्तावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। यह खदान घान-सोरनी, गड्ढरील-सोरनी, गिला-मुनेली स्थित खाना क्रमांक 5/2 एवं 6/7, खुल क्षेत्रफल-1.532 हेक्टेयर में है। खदान को आवंटित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर (ईट उत्पादन वजनई 10,00,000 नंग) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचोदना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. अधिसूचना को आपन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्ताविकरण हेतु सूचित किया गया।

विषय सूची -

(अ) सनिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023

अस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम तुलार प्रजापति, प्रोफेसर्डर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, अस्तुत जानकरी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

६. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खनन क्रमांक ६/२ एवं ६/७, कुल क्षेत्रफल-१.६३२ हेक्टेयर, क्षमता-१,००० घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्रक्रिकरण जिला-मुंगेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक २२/०१/२०१६ को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से ५ वर्ष हेतु वैध रही।

परिचालना प्रस्ताविका द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

⁹⁹9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112



for the purpose of calculation of the period of validity of Pre-Environmental Clearances granted under the provisions of the notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तापक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 352/खलि-2 ज.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/04/2018 से 31/03/2019 तक	560
01/04/2019 से 31/03/2020 तक	982
01/04/2020 से 31/03/2021 तक	970
01/04/2021 से 31/03/2022 तक	970
01/04/2022 से 28/02/2023 तक	800

दिनांक 28/02/2023 के उपरान्त किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की अधिगत जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत लोन्गी का दिनांक 16/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — खारी प्लान एक्सन प्लान खारी उत्खनन प्लान एण्ड इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (स्थान प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-माटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1106/खलि/तीन-3/2017 बलौदाबाजार-माटापारा, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 354/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 353/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर

श्री चरिद्वि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, भवन, धार्मिक स्थल, स्कूल, पुस्तकालय, बाग, मल जल-योग्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी 100 मीटर एवं मुहानाम 150 मीटर दूर है।

6. लीज का विवरण - लीज श्री श्याम कुमार प्रजापति के नाम पर है। लीज की 30 वर्षों अवधि दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 5/2 श्री श्याम कुमार प्रजापति व श्री दीपक प्रजापति एवं भूमि खसरा क्रमांक 8/7 श्री रामकुमार के नाम पर है। उत्खनन के संबंध में श्री रामकुमार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में श्री दीपक प्रजापति का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-लोरनी 1.18 किमी., स्कूल ग्राम-लोरनी 200 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-लोरनी 1.53 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19.06 किमी. एवं राज्यमार्ग 1.6 किमी. दूर है। मरियावा नदी 170 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निर्धार नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलॉजिकल रिजर्व 30,840 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 28,600 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा गहरी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 670 वर्गमीटर है। खनन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। नैच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत बल्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की समाप्ति आयु 28.6 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित कठारी पत्तन अनुसार वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	सप्तम	1,000
द्वितीय	1,000	अष्टम	1,000
तृतीय	1,000	नवम	1,000
चतुर्थ	1,000	दशम	1,000
पंचम	1,000		



13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति नगर पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की गहराई में 100 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 12,768 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,01,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,200 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,50,000 रुपये एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,40,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 5,11,028 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 9,85,376 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में 1,000 घनमीटर क्षेत्र को चिमनी स्थापित होने एवं 350 घनमीटर क्षेत्र में वृक्ष होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित असांश एवं देशांश के आधार पर मूल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी गहराई का कुछ भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पड़ा गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सर्वेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि चिमनी गहराई (चिमनी चिमनी) को डिस्क्रेट कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा गहराई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संबंधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at, Nagar panchayat - Lormi	
			Pavitra Van	8.51
			Nirman	
			Total	8.51

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (गैर, पीपल आम, कस्तूर, कदम, जामुन, आंवला, अमलताष, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 850 नम पीछों के लिए राशि 84,600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,390 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,40,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,91,990 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,59,520 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु नगर पंचायत जोरखी की शासकीय

भूमि खसरा क्रमांक 2/1, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टर भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यवस्था से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानचूच में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 28/02/2023 के तयार किए गए उत्खनन की वास्तविक मापों की अवगत जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से कंप्यूटर, फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का कुछ भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, संरक्षण प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। अतः चिमनी भट्टा (चिमनी विभाग) को डिस्मिटल कर लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. एक लाख ईट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं हमारा से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सहम प्रधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रक्त-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं भलाई देश के उचित रक्त-रखाव के लिये टिन शीट का उपयोग किया जाएगा।
10. ईट को पकाने के लिए ईट भट्टों में केवल गिर-जंग तकनीक या वर्टिकल शीफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से प्युजिटिव इस्ट उत्खनन होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल सिंचनाय की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन गृहाराखण किये जाने एवं संचित क्षेत्रों (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत याउम्पूरी पिल्लर द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कन्सेशन खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार खनन स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, छलाब, पोखर, झरना, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. पर्यावरण जागरूक पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्रशिक्षण के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलसंधन का प्रकाशन लंबित नहीं है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव जांचकन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विभिन्न वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के चलसंधन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
22. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल हिप्स या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
23. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, धुवि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, बैटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिष्ठान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना जल नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 18 नम वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई लक्ष्य प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया नहीं गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं कटाई ऐरा के संचित रख-रखाव के लिये टिन रोड का उपयोग किये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
10. ईट बने पकाने के लिए ईट भट्टों में केवल ज़िग-जैग तकनीक या बर्टिकल शीफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से धुआँ/डिस्ट डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित वृक्षों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री मिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन करके खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार सभी स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का घुमिा जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटिस से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरावन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव कायदालन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिक कानूनी एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेगे।
21. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उत्तरावन का दोषी पाये जाने पर वह भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
22. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल जिमी या कोल माइन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
27. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कुमि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा सार्वजनिक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पैटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
23. उत्तरावन के निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईट मट्टे में स्पाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटमीन) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
28. ईट मट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
24. कच्चे माल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को डंक बार रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-भाषी समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रधानिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्रधानिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-भाषी समिति से समाप्त करवाया जाना आवश्यक है।
26. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सेक्रेटरी नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र बाण्डेय विक्रम माता सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 जीफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all an from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नम वृक्षों की प्रजातियों की जानाकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उसमें वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सहम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के लिये रख-रखाव के लिये टिन शीट का उपयोग किया जाएगा। एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
4. ईट को पकाने के लिए ईट भट्टों में केवल जिन-जिम तकनीक या पार्टिकल शॉपट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह सभी मान्य होगी तथा उनको द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा। जानकारी प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
6. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल नाईन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
7. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
8. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईट भट्टों में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं फ्लैपडोर) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए.

छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्थिरता की सफल अनुशासना की जाती है।

9. ईट बट्टे से निकलने वाले गंध का उपयोग इसी परिष्कार में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने वाला रासायनिक पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्वजनिक अनुमति की जाती है।
10. कच्चे माल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को ढक कर रखे जाने वाला रासायनिक पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्वजनिक अनुमति की जाती है।
11. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पूर्व में जारी ईट बट्टे एवं मिट्टी उत्खनन हेतु जल एवं वायु संभालन सम्मति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्वजनिक अनुमति की जाती है।
12. आवेदक - मैसर्स श्याम कुमार प्रजापति प्रिवेट (प्रा.- श्री श्याम कुमार प्रजापति) को घाग-जोरमी, तहसील-जोरमी, जिला-सुरेस्ली के खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7 में स्थित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1,532 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 17/11/2025 को सम्पन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार दिग्दर्श उपरोक्त समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आदेशक — मैसर्स श्याम कुमार प्रजापति लिमिटेड (श्री- श्री श्याम कुमार प्रजापति) को ग्राम-लोरनी, तहसील-लोरनी, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7 में स्थित निम्नी उत्खनन (गोप्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.532 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया—

1. ईट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले पत्ताई ऐश का स्रोत की जानकारी (जैसे चालान, वै-बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करें कि पत्ताई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।)
2. वृक्षारोपण का रख-रखाव निर्धारित योजना को तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि परफलसादर 90 प्रतिशत हो।

स्वायत्त ही समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

2. मेसर्स खमरीध कृशर स्टोन म्बारी (प्रो- श्री राजेश कुमार मिश्रा), ग्राम-खमरीध, तहसील-मत्तापुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2567)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजित संख्या - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435241/
2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संभावित साधारण पाथर (पीण खनिज) खदान खदान ग्राम-समरौध, तहसील-भरतपुर, जिला-बोर्निया स्थित खसरा क्रमांक 717, कुल क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-7,398.3 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. प्रतीसमझ के आपन दिनांक 04/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 12/08/2023।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा भस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में पाथर खदान खसरा क्रमांक 717, कुल क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर, क्षमता-2,848.5 घनमीटर (7,398.3 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला पर्यावरण समन्वय निदेशन प्रधिकरण, बोर्निया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अवधि दिनांक 09/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"BA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर जटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार पुनरावेक्षण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलकत्ता (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 115/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.डी. दिनांक 10/08/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	775.00
2019-20	1,454.00

2020-21	505.00
2021-22	26.00
2022-23	28.00

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क़ाबाद न्यायना के संकेत में ग्राम पंचायत खमरीध का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के कार्यवाही नियम की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - क़ाती प्लान एलांग विषय क़ाती क़लीज़र प्लान विषय इन्वायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अडिक्नरी, जिला-कोरिया के पुरापन क्रमांक 875-8/खनिज/खनि2/2018 कोरिया, कैपुणपुर दिनांक 03/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 114/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.डी. दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 114/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.डी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज श्री राजेश कुमार मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षी अर्थात् दिनांक 07/03/2013 से दिनांक 08/03/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। सत्यसत लीज सीड 25 वर्षी अर्थात् दिनांक 07/03/2018 से दिनांक 08/03/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वनपरिक्षेत्र अधिकारी, बहारासी के सातन क्रमांक/622 दिनांक 17/10/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 1.5 कि.मी. या उससे अधिक है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए वन मन्त्रालय से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय उप-संभालक (वन्ध्यावनी) से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-खमरीध 1.5 कि.मी., स्कूल खमरीध 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नेपार नदी 4 कि.मी. दूर है। लीज क्षेत्र के अंदर मंदिर स्थित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उक्त खनन प्रक्रिया से मंदिर को कोई आहत नहीं होगी।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकल पोल्स्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जिमोलोजिकल रिजर्व 4,77,750 टन, माइनेबल रिजर्व 83,517 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 75,185 टन है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थिति में जिमोलोजिकल रिजर्व, माइनेबल रिजर्व एवं रिकवरेबल रिजर्व की गणना किया जाना आवश्यक है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,629 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमी गेकीनाईयड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर (4.5 मीटर हिलस्लीक एवं 5 मीटर गहराई) है। वर्तमान स्थिति में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्वारर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,390 वर्गमीटर है। जैव हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षावा प्रस्तावित उत्खनन का वितरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,474.00	षष्ठम्	7,042.10
द्वितीय	6,585.80	सप्तम्	7,075.50
तृतीय	6,649.50	अष्टम्	7,121.40
चतुर्थ	6,687.20	नवम्	7,195.50
पंचम	6,942.00	दशम्	7,398.30

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। समिति का मत है कि घास पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त ग्रामसकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **गैर माइनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर 1,829 वर्गमीटर क्षेत्र को अन्य लीज क्षेत्र होने एवं 7,447 वर्गमीटर क्षेत्र को मंदिर के कारण गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माइनिंग प्लान में किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षों तक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु पर्याप्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन एवं क़ब्रार स्थापना के संबंध में प्रस्तुत प्राप्त पंचायत समीति का अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए वन मण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया एवं आवेदित क्षेत्र की निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए संयोजित उद्य-संघालक (वन्यप्राणी) से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति में जियोलाजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व एवं रिकवरेबल रिजर्व की मंजूर किया जाए।
5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
6. सीज क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के स्थान पर राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु पीछी का रोपण, कंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा पक्क-संचाय के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु जागृता विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उद्यत खनन प्रक्रिया से जार्मिक स्थल को कोई आहत नहीं होगी।
9. पर्यावरणिक सस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग सीज क्षेत्र के अंदर स्थल वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. उत्तरीसंगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय स्तरों को रोजगार किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियंत्रण के तहत बाउण्ड्री विल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए, कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/उद्यान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में खरित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत कि जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 को अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान के लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गए हैं उसके संबंध में द्वारा प्रस्तुत किये गये जावाब और जानकारीयों के अनुसार निराकरण किया जाएगा।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 06/08/2024 एवं 27/01/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एसईएसी, छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 03/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्र, वीपआईएर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राणपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अधारत है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/08/2022 में समता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता को संकेत में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण समता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. उत्खनन एवं कला स्थापना के संबंध में प्रस्तुत राम पंचायत दुधारी का दिनांक 15/04/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही निवरण सहित) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही वर्तमान राम पंचायत खमरीय दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला-मनेन्द्रगढ़ को छापन क्रमांक/रा.आ./2024/1705 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 18/07/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 से 2 कि.मी. की दूरी पर है। 10 कि.मी. की परीमि में कोई नेशनल पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण स्थित नहीं है।

10. माइनिंग लीज क्षेत्र की ऊंदर राखन वृक्षारोपण किये जाने एवं सीमित पौधों सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलज नियमों के तहत बाचमंडी पिल्लसे द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इन परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्संघन का प्रकल्प लंबित नहीं है।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 (2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. समिति का मत है कि सीईआर एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति को सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
18. माननीय एन.जी.टी. ऑरिजनल डेव नई दिल्ली द्वारा सर्वोद धामडेव विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

	एवं 423/3 श्री लक्ष्मीचंद मरावी, खसरा क्रमांक 415/2 श्रीमती सुकनगी, श्री लीकनराम, श्री सुनीलराम, श्री अनंतराम, श्रीमती गोमती बाई, श्रीमती सुनीता बाई एवं श्रीमती अनिता बाई, खसरा क्रमांक 414/2 श्रीमती फिरन, खसरा क्रमांक 407/2 श्री मुहसिंह एवं श्री महमूदाल, खसरा क्रमांक 407/3 श्री हरीसिंह, खसरा क्रमांक 408 श्री प्यारेलाल, खसरा क्रमांक 411 एवं 413 श्री भागीरथी छोटेवाल, खसरा क्रमांक 416 श्री लक्ष्मीचंद, खसरा क्रमांक 417 श्री लक्ष्मीचंद के नाम पर है।	स्वामी का सहमति पत्र है।
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विकास कोटिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पुर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – बीजोमाईट (मौम खनिज) खसरा क्रमांक – 408, 407/1, 407/2 एवं अन्य क्षेत्रफल – 4.747 हेक्टेयर क्षमता – 99,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 09/12/2018	सी ई आई.ए.ए. भिला-जांजगीर-बांग्ला पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/02/2048 तक है।
पुर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	रव-प्रमाणित – हो क्षमता विस्तार के तहत – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर – अछाप्त	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 500 वन भूमि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पुर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 08/01/2024 2018-19 में निराक 2019-20 में 32,000 टन 2020-21 में 89,000 टन 2021-22 में 83,880 टन 2022-23 में 62,850 टन 2023-24 (तिसांघर तक) में 300 टन	अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की वारंवारिक मात्रा की अधिमान जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करताकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ब पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत लोहराकोट दिनांक 12/07/2008	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 29/09/2023	
500 मीटर	दिनांक 21/07/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 21/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं माचनर बाहर 30 मीटर दूर है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक - श्री द्वारिका गुप्ता, आगो - दिनांक 23/02/2018 से 22/02/2068 तक।	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवधिक क्षेत्र को निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - लोहराकोट 350 मीटर स्कूल ग्राम - लोहराकोट 380 मीटर अस्पताल - सब्जी 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 7.7 कि.मी. राज्यमार्ग - 8.8 कि.मी.	बोर्ड नदी - 4.5 कि.मी. बासा - 1 कि.मी. तालाब - 770 मीटर नहर - 30 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	6 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्ड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निर्धार नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - डी सिर्जस- जियोलाजिकल 14,99,790 टन माईनेबल 8,29,727 टन रिकवरेबल 7,46,754 टन प्रस्तावित गहराई 22 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संचालित आयु 3 वर्ष स्थापित करार - नहीं वर्तमान में प्रस्तावित करार - नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 99,950 टन द्वितीय 1,46,732 टन तृतीय 1,00,013 टन चतुर्थ 2,00,003 टन पंचम 2,00,014 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 4,981 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल - 1,560 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - नहर 30 मीटर की दूरी में होने के कारण	माईनिंग प्लान में उत्खनित - डी
ऊपरी मिट्टी/	मोटाई - 2 मीटर	2,766 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईनिंग)

		6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपना पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑपिनियन में दिये निर्देश का विन्योदक पालन किया जाएगा।
बेनी	बी2	आयोजित खदान का कुल क्षेत्रफल 4.747 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.95	2%	1.13	Following activities at Nearby, Village- Lohrakot	
			Plantation around village pond	1.55
			Total	1.55

2. बीडूआर के अंतर्गत तालाब की घाटी और वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 120 नव पौधों के लिए राशि 12,000 रुपये, फीसिंग के लिए राशि 18,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 8,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रुपये हेतु धटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहारकोट के सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 245, क्षेत्रफल 0.534 हेक्टेयर में विद्यत तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकिकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नयापूर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबद्धता प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाए।
3. आयोजित क्षेत्र की इन क्षेत्र एवं अभ्यास्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय जनसम्पर्क अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन योजना - मॉडिफाईड स्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतवाड़ा के आपन क्रमांक 362/खनिज/2018-19 दंतवाड़ा, दिनांक 01/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकर के आपन क्रमांक 1134/खनिज/उ.प./2018-20 कांकर, दिनांक 28/02/2020 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकर के आपन क्रमांक 1133/खनिज/उ.प./2018-20 कांकर, दिनांक 28/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनोकेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं सीमा का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। सीमा मोहम्मद जावेद के नाम पर है। सीमा डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/12/1998 से 15/12/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् सीमा डीड में 10 वर्षों की, दिनांक 16/12/2018 से 15/12/2028 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य), जिला-उत्तर बस्तर कांकर के आपन क्रमांक/482, दिनांक 13/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अधस्तन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम जावादी ग्राम-खैरखेड़ा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-खैरखेड़ा 1 कि.मी., एवं अस्पताल ग्राम-लखनपुरी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकल नॉ-बुल्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन शोल्दा एवं खनन का विवरण - जिब्रोलाइटिकल रिजर्व 18,42,898 टन एवं साईनेबल रिजर्व 8,21,520 टन है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,100 वर्गमीटर है। आपन कार्ट सीमा मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई कुल 30 मीटर है, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्र 9 मीटर है। सीमा क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गांज 1,500 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर बुधारावण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। सीमा क्षेत्र में कचरा स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डिज़ींग एवं कंट्रोल प्लान्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण

4. लैंड सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय वनसम्पदाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान स्थिति में जियोलाजिकल रिजर्व एवं नाईनेबल रिजर्व की प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

संदानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2023 के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कमिशन, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि यह सामग्य विस्तार का प्रकरण है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिशियल मेमोरैण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार "At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same." है। इस संकेप में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अदालत नगर से मंगाया जाना आवश्यक है।
2. परखनन हेतु राम पंचायत खैरखेड़ा का दिनांक 20/11/2023 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार धूआरोपम इसी मानसून में करते हुए पीपी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोकॉपी सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, कांकेर वनसम्पदा, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2024/764 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 260 मीटर की दूरी पर है।

5. वर्तमान स्थिति में जिपोजैलॉजिकल रिजर्व एवं साईनेबल रिजर्व की प्रभावि जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अदालत नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछों के नाम का जलवेष्ट किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान स्थिति में जिपोजैलॉजिकल रिजर्व एवं साईनेबल रिजर्व की प्रभावित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग फ़्यूजिटिव डस्ट कंट्रोलिंग नियंत्रण, सड़क वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियंत्री के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के सैफ्टी जोन में रख कर वृक्षारोपण करने, ओवरबर्डन को खनिज विभाग के सहमति से विक्रय करने आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने तथा सीईआर के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जिपोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई एल्लेगेशन का प्रकरण ललित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिसा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्रवाही की जाएगी।
एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/01/2025 एवं 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 845वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अडलौकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 675, दिनांक 29/06/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कर पीछी का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। परंतु निर्धारित कर्तानुसार वृक्षारोपण पीछी का संख्यांकन (Plantation) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.प्र. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 134, दिनांक 16/01/2025 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2022-23	2460	4,034.4
2023-24	880	1,443.2
2024-25 (नवम्बर 2024 तक)	280	459.2

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 18,42,696 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,21,320 टन तथा वर्तमान स्थिति में आरक्षणी द्वारा किये गये गणना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 18,09,291 टन एवं माईनेबल रिजर्व 7,87,825 की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.4	2%	0.768	Following activities at Govt Primary School Village- Khaikheda	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.40
			Running Water Facility for toilets and kitchen	0.40
			Total	0.80

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कन्ट्रोल ब्यारिस्टिंग, मयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सफ्तन पुनारोपण एवं 60 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छातीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक प्रात स्वोर्ती के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, छपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के सफटी जोन में रख कर पुनारोपण करने, ओवरसर्चें को खनिज विभाग के सहमति से विक्रय करने आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले पुनारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने तथा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी गिडरेग (Gidreg) कोटिंगापल सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. सगिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. छपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभरण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिए गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंदाजबंदी (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, जिला-कांकेर के आपन क्रमांक/मा.पि./2025/2014 कांकेर दिनांक 08/04/2025 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र लगभग 500 मीटर एवं जैव विविधता क्षेत्र 2 कि.मी. की दूरी पर है तथा 10 कि.मी. की परिधि में कोई मेघमल पार्क, अभ्यारण्य अस्तित्व में नहीं है।
15. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
16. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल वी. नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाम्पेड विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतिम नं. एन.जी.टी. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-खतर बख्तर कांकेर के आपन क्रमांक 1134/खनिज/उ.प./2019-20 कांकेर, दिनांक 28/02/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरूप है। आवेदित खदान (ग्राम-खैरखेड़ा) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संभावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी धानखुम में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उपलब्ध किया जाकर गिरोटिंग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एवं कंट्रोल डस्ताइंटिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized affidavit) एस.ई.आई.ए.ए., जलसीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुसंधान की जाती है।
3. मेसर्स खैरखेड़ा जीर्णोद्धार स्टोन क्वारी (प्रो.-मोहम्मद जावेद) की ग्राम-खैरखेड़ा, ताहसील-सारागा, जिला-कांकेर के खसरा क्रमांक 1828 एवं 2640/1 में स्थित सारगण पत्थर (पीपल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर क्षमता - 81,245 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुसंधान की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिन 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मशीन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनस्पतलाधिकारी, काकोर वनस्पतल, काकोर की जापान क्रमांक/मा.वि./2024/764 काकोर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 260 मीटर की दूरी पर है। माननीय एनजीटी द्वारा आवेदित एवं संरक्षित एम्प्लोय की सीमा से खदान की दूरी 01 किमी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आवेदित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दूरी का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी भी प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. कन्ट्राज् क्लैस्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया जाना होगा।

उपरोक्तानुसार जानकारी/वस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

3. मेजरस कमलेश कुमार मिश्रा अर्थ छले बजारी, ग्राम-सोनपुर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2408)

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोज़ल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430494/ 2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से जापान दिनांक 12/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/08/2023 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई, ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण में प्रस्तुत जानकारी दिनांक 17/10/2023 प्रदर्शित हो रहा है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सोनपुर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 405 (फर्टी), 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022.

In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मैमोरैण्डम के तहत परियोजना प्रसाधक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण अधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-approval) हेतु एस.ई.ए.सी. स्वीकृतिपत्र के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

तदनुसार धरियोजना प्रस्तावक को एसई.ए.सी. प्रतीसंगद के ज्ञान दिनांक 18/10/2023 ज्ञान प्रस्तीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठली का चित्रण —

(अ) समिति की 48वाँ बैठक दिनांक 26/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—

- i. पुरे में मिट्टी खदान ससरा क्रमांक 405 (पार्टी) 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर, क्षमता-2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला नारीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण, जिला-दुर्ग द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में ली गई कार्रवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित तर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक 781/खनि. ति.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये छेखन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	1,450
2016-17	1,800
2017-18	100
2018-19	1,300
2019-20	500
2020-21	2,000
2021-22	1,200
2022-23	1,400

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – ईट निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत सोनपुर का दिनांक 12/08/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



3. **उत्खनन योजना** – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिक, जिला-बालोद के पु. आपन क्र. 984-85/खनि.सि./खनिज/2018 बालोद दिनांक 04/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय बालेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक 781/खनि.सि.03/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय बालेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक 781/खनि.सि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, महल, बांध, एसीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर की परिधि में ताप्ताब एवं खास्न नदी स्थित है।
6. **लीज का विवरण** – लीज श्री कमलेश कुमार मिश्रा के नाम पर है। लीज सीड 10 वर्षों अवधि दिनांक 03/10/2013 से दिनांक 02/10/2023 तक की अवधि हेतु दिया थी। उत्प्रेषणा लीज सीड 5 वर्षों अवधि दिनांक 03/10/2023 से 23/11/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 405 (पाटी) एवं 414 श्री विनेश कुमार, खसरा क्रमांक 408 व 409 श्री विजय लक्ष्मी देव, खसरा क्रमांक 413 श्री कमलेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान के लिए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी का वार्षिक करों रूप वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सोनपुर 200 मीटर, स्कूल ग्राम-सोनपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल पाटन 3.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 154 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 870 मीटर दूर है। खास्न नदी 132 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलाजिकल रिजर्व 30,000 घनमीटर एवं नॉइनेबल रिजर्व 18,000 घनमीटर है, वर्तमान में नॉइनेबल रिजर्व 12,566 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र)

रुपये तथा आयामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिसूचना मेंमोरैण्डम में दिये गये निर्देश का विन्मुखार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 5,000 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में नसमता किया जायेगा एवं अवशेषित बर्बे बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा का किररी भी प्रवाह का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण हेतु सौकरपिट बनाया गया है। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सधन वृक्षांशेण किये जाने एवं रोषित पौधों का सखाईवत रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाधाम्पूरी मिल्लरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. धलीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिकर्शन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधन का प्रकरण ललित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कोपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंत्राल को प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पपुजिटिव इस्ट उत्तरार्जन होगा, उन स्थलों पर निर्दिष्ट जल छिड़काव की बाबत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्तराधन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एक लाख ईट निर्माण हेतु कितने टन कोयला की आवश्यकता के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. वर्तमान में एकसीबीटी.के. क्लिन स्थापित है। एकसीबीटी.के. क्लिन से जिन-जैंग क्लिन में परिवर्तन किये जाने हेतु तकनीकी विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार को पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिसूचना मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत राष्‍ट्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 143(अ), दिनांक 22/02/2022 के अनुसार जिन-जैंग क्लिन को 02 वर्ष (अर्थात् 21/02/2024) तक स्थापित किये जाने बाबत राष्‍ट्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज सीमा से निष्‍काटन वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए कनकचलाधिकारी से जारी अनायात प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), दिल्ली-दुर्ग को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अधिलक्ष्य प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

चंपरीका व्यक्ति जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। कार्यालय बल्लेसर (खनिज
श्रेणी), पिन्ना-दुर्ग को पत्र लेख किया जाए।

एच.ई.ए.सी., अस्तीसभद श्री 483वीं बैठक दिनांक 20/10/2023 के परिप्रेक्ष्य में पत्रिचीयना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) सन्निधि सौ ६५५वीं बैठक दिनांक ०४/०९/२०२५

समिति द्वारा नमूने प्रस्तुत जानकारी का अद्यतनीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एक लाख ईट निर्माण हेतु 20 टन कीयला 50 से 60 सन्मीटर पानी एवं 200 सन्मीटर मिट्टी (100 सन्मीटर मिट्टी एवं 100 सन्मीटर पत्ताई एंश) की आवश्यकता होती है।
2. वर्तमान में एकसीसीटीके किलन स्थापित है। एकसीसीटीके किलन से जिग-जैग किलन में परिवर्तन किये जाने हेतु तकनीकी किरण प्रस्तुत किया गया है।
3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 की जारी ऑफिश मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 143(अ), दिनांक 22/02/2022 के अनुसार जिग-जैग किलन को 02 वर्ष (अर्थात् 21/02/2024) तक स्थापित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमन्त्रालय/कार्यालय, वनमन्त्रालय, जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक/उक.अधी./2024/304 दुर्ग, दिनांक 21/01/2024 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार की ईमारती, गैर ईमारती एवं फलदार वृक्ष नहीं बोया गया है तथा वनबीज से दूरी 40.00 कि.मी. पर स्थित स्वीकृत मिट्टी उत्खननपट्टा (विनमी ईट मट्टा) के उत्खननपट्टा क्षेत्र पर नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।" का उल्लेख है।
6. समिति का मत है कि सीईआर एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण विधि जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल मैम, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलिकेशन नं. 180 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक 781/खनि.नि. 02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है। आवेदित खदान (ग्राम-सोनपुर) का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स कमलेश कुमार मिश्रा अर्ध प्ले क्वारी को ग्राम-सोनपुर तहसील-वाटन, जिला-दुर्ग के खसरा क्रमांक 405 (पाट), 408, 409, 413 एवं 414 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर, समता-2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक — मेसर्स कमलेश कुमार मिश्रा अर्ध प्ले क्वारी को ग्राम-सोनपुर तहसील-वाटन, जिला-दुर्ग के खसरा क्रमांक 405 (पाट), 408, 409, 413 एवं 414 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गोण

खमिज) खदान कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर क्षमता-2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया-

- परियोजना प्रस्तावक को 01 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में 450 मग वृक्षारोपण का कार्य 06 माह में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जाये अन्यथा छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण गैजट द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जायेगा, जिसने खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
- वृक्षारोपण का रण-रखाव निर्धारित योजना के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 90 प्रतिशत हो।
- ईट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्वोत् की जानकारी (जैसे बालान, वे-बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करें कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।
- समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभिन्न वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सखत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. मेसर्स कड़मपाल आर्बिन्सरी स्टोन क्वैरी (प्री.- श्री अमन अग्रवाल), ग्राम-कड़मपाल, तहसील-बघेली, जिला-दंतोवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2986)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 457104 एवं 29/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (मीन खमिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.35 हेक्टेयर एवं 26,885 टन प्रतिवर्ष	संतुलन है।
खसरा क्रमांक	815/2	संतुलन है।
भू-स्वामित्व	राजकीय भूमि	संतुलन है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माँहिल जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2023 के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक पूर्व में जारी गई बाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नौन्दरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नौन्दरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी नगर, नया रायपुर अटल नगर को आवगत कराया गया। तदुपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी नगर, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पत्र मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचारणीय था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस नोमिनेशंस दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस नोमिनेशंस में तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समायोजन निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण
बैठक का विवरण	591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री अमन अहवाल, प्रोग्रामाईटर उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - सामान्य पथर (गीण खनिज)

पारिस्थितिकीय / संवेदनशील क्षेत्र	जैवविविधता	आरवपुटी के अनुसार 5 किमी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित लिस्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण		उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कटोल ब्लास्टिंग – हाई जियोलॉजिकल 4,20,678 टन माइनेबल 2,58,548 टन प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर (ट्रेल लीज 12 मीटर एवं 6 मीटर सतही गहराई) बेस की ऊंचाई 3 मीटर वेज की चौड़ाई 3 मीटर समाप्ति आयु 10 वर्ष क्राशर स्थापित एवं प्रस्तावित नहीं है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,264 टन अष्टम 23,264 टन द्वितीय 23,264 टन नवम 26,985 टन तृतीय 23,264 टन दशम 26,985 टन चतुर्थ 23,264 टन अष्टम 26,985 टन पंचम 23,264 टन दशम 26,985 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र		लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,412 वर्गमीटर उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्न प्रबंधन योजना		पत्थरिला क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।
जल आपूर्ति		नाला – 4 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से। ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य		लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर के घाटी ओर वृक्षारोपण – 300 गम किया गया है। लीज के 7.5 मीटर क्षेत्र पत्थरिला क्षेत्र होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत की अनुमति उपरान्त जासकीय भूमि खसरा क्रमांक 516, क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।

समिति को उत्तममय पट्टे की अवधि विस्तार करने हेतु अनुपूरक पदराशिसेख अनुकां दिनांक 03/03/2017 को किया गया है।

3. समिति द्वारा तै.एम.एल. के माध्यम से देखने पर पाया कि क़ासर का कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क़ासर को लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित किये जाने तथा क़ासर का संबंधित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु सन्मति लिये जाने बाबत बाध्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपराल निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.87	2%	0.61	Following activities at Nearby, Village-Kadampal	
			Plantation	6.301
			Total	6.301

सीईआर के अंतर्गत घास-कड़मपाल के तासखीय भूमि में वृक्षारोपण (नीम, कस्तूर, अर्जुन, कादम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीछी के लिए राशि 7,000 रुपये, पीसिंग के लिए राशि 60,600 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 72,000 रुपये, पछ-बछाव आदि के लिए राशि 30,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,91,100 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,39,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याग पंचायत कड़मपाल के सहमति उपराल यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 534, क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा उत्तममय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किए गए उत्तममय की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी समिति विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) में प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सन्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 601वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/05/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दतेवाड़ा के आपन क्रमांक 1038/खनिज/उ.प./2024-25 दतेवाड़ा, दिनांक 19/03/2025 द्वारा विगत वर्ष 2023-24 में 26.882 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दतेवाड़ा के आपन क्रमांक 73/खनिज/उ.प./2025-26 दतेवाड़ा, दिनांक 23/04/2025 द्वारा विगत वर्ष 2024-25 में 26.886 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
3. लीड क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) में प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण ड्रोन विडियो कटा पाना संभव नहीं है। अतः ड्रोन विडियो से छुट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के आपन क्रमांक 120, दिनांक 23/04/2024 द्वारा नाईनिंग एवं कंशिन ऑफ स्टोन क्षमता - 26.885 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण जारी की गई है।
5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी. डिस्ट्रिक्ट डेप्ट, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विक्रेता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-कडमपाल) का क्षेत्रफल 1.35 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. मेसर्स कडमपाल आर्किनरी स्टोन क्लारी (प्रो- श्री जमन अशवाधर) को ग्राम-कडमपाल, तहसील-बघेली, जिला-दतेवाड़ा के खसरा क्रमांक 815/2 में स्थित साधारण पत्थर (पीपल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.35 हेक्टेयर, क्षमता - 26.885 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुरक्ता की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 215वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनोद्योग वनमण्डल वनोद्याया द्वारा जारी दिनांक 05/02/2024 परिक्षेत्र अधिकारी बगैरों की प्रतिवेदन अनुसार "आवेदित स्थल आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन या नारंगी क्षेत्र के 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
2. नाननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित वन संरक्षित वनोद्योग की सीमा से खदान की दूरी 01 किमी. के भीतर नहीं दिखे जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दूरी का आदेश प्राप्त होने के पर्याप्त प्रकरण पर पुनर्विचार किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घास पशुपत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण किये जाने की जानकारी दी गई है। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य स्त्रीत में होने वाले धूल रास्तजन को रोकने के लिए है। अतः 7.5 मीटर या लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति होती है ना कि किसी अन्य क्षेत्र में करने से। अतः परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र के बाहरी तरफ में उपयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
4. वृक्षारोपण का कार्य 05 माह के भीतर में किया जावे अन्यथा उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्त का पालनन पाये जाने पर निधमनुसार कार्यवाही किया जावेगा जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

संबन्धीतानुसार जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर तत्कालीन कार्यवाही की जायेगी।

7. मेसर्स वी.वी. कव्हार स्टोन, आर्टिगरी स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री वशिष्ठ कश्यप), ग्राम—जुनवाणी, सहस्राल—नरहस्थर, जिला—कांकोर (सचिवालय का मस्ती क्रमांक 2479)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन समूह - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431045/
2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्थिति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संजालित साधारण फल्टर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम—जुनवाणी, तहसील—नरहटपुर, जिला—कांकेर स्थित खदान क्रमांक—298, कुल क्षेत्रफल—1.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—44,931 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचीजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रत्युत्तरित हेतु सूचित किया गया।

विद्यार्थी का विवरण—

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषदीयता प्रस्तावक की पक्ष दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अंगुर्न होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। ततः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

	वर्ष 2021-22 में 3,515 एकड़ और वर्ष 2022-23 में 2,980 एकड़	वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
घास पैदावार एन.ओ.सी.		अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पठनीय नहीं है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10/06/2016	
500 मीटर	दिनांक 25/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/05/2023	अवधि - 100 मीटर
लैंड डीड	लैंड डीड अपठनीय है।	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल कार्पेस द्वारा जारी ह्रासन दिनांक 20/06/2007 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	आवृत्त क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उत्तरेष्ट करने हुए कार्पेस वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आवादी - वनार 1.2 कि.मी. स्कूल - वनार 1.2 कि.मी. अस्पताल - छावनी 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 10 कि.मी. राज्यमार्ग - 8 कि.मी.	महामादी - 3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइण्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लेस्टिंग - डो रिजर्व - जियोलॉजिकल - 8,70,875 टन माईनेबल - 3,98,816 टन प्रस्तावित गहराई 12 मीटर बेस की ऊंचाई 3 मीटर बेस की चौड़ाई 3 मीटर संगठित आयु 10 वर्ष कणश प्रस्तावित - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,070 टन द्वितीय 32,310 टन तृतीय 16,832 टन चतुर्थ 44,931 टन पंचम 44,931 टन षष्ठम 44,931 टन साप्तम 44,931 टन अष्टम 44,931 टन नवम 44,931 टन दशम 44,931 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सारकृत जियोलॉजिकल प्लान अनुसार उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का कुछ भाग असंभवित है।	कवारी प्लान अपठनीय है।

कंपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना		कंपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	साठा - 4 स्त्रीता - होनवेल	सिन्ट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	सीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के सरों और वृक्षारोपण - 768 नम किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 12,30,680 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लाकिंग, पर्युजिटिव डक्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सड़क वृक्षारोपण एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि वाक्य शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मैटेरियल कुल मात्रा 5.810.2 को आवश्यकतानुसार रखते की मरम्मत में उपयोग किया जावेगा, अतिरिक्त बचे हुए को खनिज विभाग की सहमति से बेचा किता जावेगा।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, धर्मोपकरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.जा 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरदायन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का गैर द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
क्षेत्री	बी-2	अवैधित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1.7 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से बर्दा उपरांत विमानानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.50	2%	0.89	Following activities at Government Middle School Village- Junwani	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (पीपल, नीम, आम, जामुन एवं कदम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, छाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,800 रुपये हेतु परतकावर आम का विकल्प प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सन्मति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के फालन में की गई कार्यवाही हेतु फालन प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी ई.सी. के तहत निर्धारित शर्तानुसार 575 नम पीधों का वृक्षारोपण कर नमरदिन एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26/12/2015 से दिनांक 31/03/2018 तक एवं दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करणकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम पंचायत जुनवानी का (बैठक दिनांक, सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित) पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड (लीज धारक, कैप्ता अवधि सहित) की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. क्वारी प्लान का पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यदि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिनियमित क्षेत्र) में उत्खनन किया गया हो तो इस संबंध में रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (मोटाई एवं मात्रा सहित) योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. आवेदित क्षेत्र की निकटतम नन क्षेत्र से दूरी का जलनेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनायति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वारित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 502 वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025

समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, धन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में अमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण अमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों की धारण के संबंध में स्व-अनुपालन प्रमाण पत्र (Self-compliance report) प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी ई.सी. के तहत निर्धारित सार्तानुसार 525 नग बीघों का वृक्षारोपण कर सम्बन्धित एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.प्र. कांकर के आपन क्रमांक 1721/खनि-1/उ.प्र./न.क./2007 कांकर, दिनांक 18/09/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार पिगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016-17	1.700
2017-18	10.467
2018-19	6.840
2019-20	5.160
2020-21	5.900
2021-22	3.515
2022-23	2.860
2023-24	1.500

4. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जुनवाही का दिनांक 04/04/2007 का अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज मेसर्स पी.पी. कपूर स्टोन के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अवधि दिनांक 17/11/2007 से 16/11/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मीट्रिकाईड नक्शे प्लान, प्लॉग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इम्प्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-अमराठी के आपन क्रमांक 888/खनि.3/अ.प्र./2024 धमतरी, दिनांक 20/09/2024 द्वारा अनुमोदित है। साथ ही यदि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के उत्तर दिशा की तरफ 882 वर्गमीटर 2 मीटर की गहराई एवं पूर्व दिशा की तरफ 1,288 वर्गमीटर 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनर्भरण हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पुनर्भरण हेतु राशि 3,08,100/- खर्च किया जाना प्रस्तावित है।
7. लीज क्षेत्र में कुल 3,012 घनमीटर मोटाई 1 मीटर कपरी मिट्टी उत्खनन होगा जिसका उपयोग पुनर्भरण एवं लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण कार्य में किया जाएगा।

8. कार्यालय नव मण्डलधिकारी कार्फोर वन मण्डल कार्फोर के आपन क्रमांक/मा./2024/1682 कार्फोर दिनांक 05/03/2024 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र से संक्षेत्र 1.17 किमी. की आवासीय दूरी पर है।
9. समिति का मत है कि सीईआर एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-पक्षीय समिति (प्रोपरईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं विजा प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्रशासिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
10. माननीय एन.जी.टी. डिप्टिपल बीच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-जुनवाणी) का क्षेत्रफल 1.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. मेसर्स पी.पी. क्लार स्टोन, आर्जिनरी स्टोन खारी (प्रो- श्री यशिष्ठ कश्यप), को ग्राम-जुनवाणी, तहसील-नरहत्पुर, जिला-कार्फोर के खसरा क्रमांक 298 में स्थित साधारण पत्थर (गीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टेयर, क्षमता - 44,831 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मंजूरी का अभिलेखन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स पी.पी. क्लार स्टोन, आर्जिनरी स्टोन खारी (प्रो- श्री यशिष्ठ कश्यप), को ग्राम-जुनवाणी, तहसील-नरहत्पुर, जिला-कार्फोर के खसरा क्रमांक 298 में स्थित साधारण पत्थर (गीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टेयर, क्षमता - 44,831 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-
1. परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कुल 768 मग वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

- ii. परिशिष्ट-2 में प्रस्तावित द्वारा मीडियापार्टीट क्वार्टी प्लान, एलाय विथ नार्दन क्लीज प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सनि अधिकारी, जिला-धनतरी के आदेश क्रमांक 688/ख.सि.3/स्था/2024 धनतरी, दिनांक 20/08/2024 द्वारा अनुमोदित है। 7.5 मीटर चौड़ी रोमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित होव) के उत्तर दिशा की तरफ 882 वर्गमीटर 2 मीटर की गहराई एवं पूर्व दिशा की तरफ 1,288 वर्गमीटर 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को संबंधित योजना के अनुसार पुर्नभरण एवं उस पर वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- iii. वृक्षारोपण एवं पुर्नभरण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जाते अन्यथा घनत्वसंगत पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शां का उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही की जा सकती है।

साथ ही समिति द्वारा विहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावना को सहार्त धर्मावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

8. मेरस मिलधरा आर्जिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग मिट्टी (प्रो- वी गजेन्द्र जींग), ग्राम-मिलधरा, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर (सचिवालय का नरती क्रमांक 1715)
जीनलार्जिन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/
217297/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पथर (गीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मितावरा, तहसील-मगीधा, जिला-जयपुर स्थित खसरा क्रमांक 967/1, कुल क्षेत्रफल-0.75 हेक्टर है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-34,488.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई थी।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — जखनन ही संस्थान में ग्राम पंचायत निताघरा का दिनांक 18/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



3. **उत्खनन योजना** – कार्यालय प्रस्तुत किया गया है, जो सप संचालक (खनन), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक क/975/खनि.-2/2021 रायगढ़, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/57/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विद्यवापीन खदान के सीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (समा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक सीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिजस मिनेरल क्षेत्र में विद्यवापीन खदान के सीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के सीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/58/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनोकेट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कलेक्टर जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 438/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2021/269 जशपुर, दिनांक 23/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **गहनपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासीय ग्राम-मितधरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-मितधरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बगीचा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.5 कि.मी. दूर है। जोरकी नदी 1.25 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जिब्रोल्तीजिकल रिजर्व 2,04,750 टन, नाईगेरल रिजर्व 68,936 टन एवं रिकॉन्स्ट्रुक्शन रिजर्व 62,042 टन है। सीज की 7.5 मीटर मोड़ी सीमा गड्ढी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,025 वर्गमीटर है। जोपन कार्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। सीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा गड्ढी (7.5 मीटर) में फैलाकर पुनरावेषण के लिए उपयोग किया जाएगा। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। सीज क्षेत्र में ज़ावर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षावात प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित पत्रचनन (टन)
प्रथम	34,400
द्वितीय	34,400

नोट: तालिका में दशमसह के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़कन, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित विभिन्न खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस शर्त पर ग्राम पंचायत का अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं पहुंच मार्ग में 800 नर वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Middle School, Village - Bhitphara	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for flushing and washing Toilets	0.20
			Total	0.80



समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:-

1. माईनिंग विभाग से कलक्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी उपरोक्त विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बाढ़लक्षित अभ्यारण्य की वास्तविक पूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा एवं उसके संस्कारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 383वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नवीं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (व्यमिज शाखा), जिला-जशपुर के ड्राफ्ट क्रमांक 171/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जिला-जशपुर के ड्राफ्ट क्रमांक/मा.वि./2021/3173 जशपुर, दिनांक 16/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. एवं बाढ़लक्षित अभ्यारण्य से 5 कि.मी. दूर है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा 2,437.5 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं संस्कारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. परियोजना हेतु खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंचकाय, प्लास्टोपण) हेतु जल की आपूर्ति बीरसेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु संपूर्ण बाढ़लक्षित वॉटर अधॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं संस्कारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 27/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेन्द्र जैन प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. त्रिखंडा क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खज.) जिला-रायगढ़ के पु ज्ञापन क्रमांक 2240ए/ख.लि.-2/2021 रायगढ़, दिनांक 06/11/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोमॉर्फिकल रिजर्व 2,04,750 टन (78,750 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 56,550 टन (21,750 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 50,895 टन है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की संभारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 885 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा के 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 2.58 मीटर की कबाई तक संरक्षित कर रखा जाएगा।
2. समिति के संज्ञान में यह लब्ध आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. ऊपरी मिट्टी कन्जर्वेशन प्लान को परियोजना लागत में सम्मिलित कर कुल परियोजना व्यय प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 17/10/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 को माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. खदान से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 885 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा में 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 1 मीटर की कबाई एवं 28 डिग्री स्लोप में ढुंढ किया जावेगा। साथ 1280 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्ता

मुनि खसरा क्रमांक 648/3 एकका 6070 वर्गमीटर में 1 मीटर की ऊंचाई एवं विधि में अन्य किया जाएगा।

2. न्यायालय नगर न्यायाधीशद्वारा, बगीचा, जिला-जशपुर के आपन क्रमांक 420/वापस/2024 बगीचा दिनांक 10/10/2024 द्वारा लीज क्षेत्र का विस्तार एवं सीमांकन बाबत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. रिकॉर्डरवल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला-जशपुर के आपन क्रमांक 435/ख.श./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की तक वैध थी। अब एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संग्रहीत हो गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत जानकारी संबंधित वन विभाग से अनामत प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.एस. छत्तीसगढ़ के 684वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 एवं आपन दिनांक 03/06/2025 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 29/05/2025 एवं दिनांक 23/07/2025 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(3) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नवरी, प्रस्तुत जानकारों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, नौमिकी तथा खनिकर्मा नारायणपुर अदालत नगर के मुखरीक्षण प्रकरण क्रमांक 48/2024 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 18/08/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ जिला कार्यालय, जशपुर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 58 के तहत उत्खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृति हेतु दैनिक पर्यावरण सम्मति के साथे प्रारूप बाईंस में जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 10/02/2021 त्रुटिपूर्ण है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। उक्त आवेदन को जीवित मान्य किया जाकर आवेदक श्री गजेन्द्र जैन आत्मज स्व. श्री सेठमल जैन निवासी कुनकुरी के नाम पर निर्माण विभाग का वैध कार्यदेश वर्तमान में जीवित होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा पर्यावरण सम्मति से संबंधित सभी अनामत प्रमाण पत्र प्राप्ति अपराध नियम 58(1)(पांच) के तहत स्वीकृति आदेश प्रारूप बाईंस में जारी किया जाना होगा। उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आशय पत्र की समय-सीमा निर्धारित न होने से इसकी वैधता स्वयं प्रचलनशील है।

सम्यक रूप से विचारोपरांत प्रस्तुत उत्खनन अनुज्ञापत्र आवेदन को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति की स्थिति में जीवित मान्य किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल जिला-जशपुर, के आपन क्र./स. वि./2025/3850 जशपुर दिनांक 12/08/2025 से जारी अनामत प्रमाण पत्र

अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम जन क्षेत्र की सीमा से 01 कि.मी. वन्यजीव सम्धारण गूगल अर्थ के आधार पर लगभग 2.50 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र क्षेत्र की सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।

3. समिति का मत है कि सीईआर एवं वृक्षारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यावेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अस्तीनगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. कार्यलय कलेक्टर (अनिज शाखा), जिला-जयपुर की ड्राफ्ट क्रमांक/67/स.अ. /2021 जयपुर, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। खानगी एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेध, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (इंजिनेयर एपिलिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को गति आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक — मेसर्स मितधरा आर्जिनरी स्टोन साईन फॉर मेकिंग मिट्टी (प्रो.— श्री राजेन्द्र जैन) को ग्राम-मितधरा, तहसील-बगीचा, जिला-जयपुर के खसरा क्रमांक 907/1 में स्थित साधारण पत्थर (गीण अनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर, क्षमता-34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2020 को सम्पन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुमति के स्वीकार करते हुए आवेदक — मेसर्स मितधरा आर्जिनरी स्टोन साईन फॉर मेकिंग मिट्टी (प्रो.— श्री राजेन्द्र जैन) को ग्राम-मितधरा, तहसील-बगीचा, जिला-जयपुर के खसरा क्रमांक 907/1 में स्थित साधारण पत्थर (गीण अनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 0.75 हेक्टेयर, क्षमता-34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभिन्न वैधानिक एवं सम्बलक कार्यवाही की जाएगी।

परिशीलना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

9. मेसर्स ओके डिवेलप एण्ड ट्रांस्पोर्ट (प्रो.- श्री यतीन्द्र कुमार खत्री), ग्राम-गुलसाघाट, तहसील-जोरगी, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2379)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/425143/2023 दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गुलसाघाट, तहसील-जोरगी, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 61/1/अ, कुल क्षेत्रफल-2.31 है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,500 घनमीटर (15,00,000 लिटर्स) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 23/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यतीन्द्र कुमार खत्री, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान खसरा क्रमांक 61/1/अ, कुल क्षेत्रफल-2.31 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघट निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"BA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार कृतारीपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के द्वारा क्रमांक 347/खनि.-2 ड.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

राष्ट्रीय राजमार्ग 69 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। सभियारो नदी 1 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली बील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलाजिकल रिजर्व 46,200 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 41,318 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 701 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर क्षेत्र में ईट निर्माण हेतु भण्डार स्थापित है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पत्ताई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 27.5 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्लारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500	षष्ठम	1,500
द्वितीय	1,500	सातम	1,500
तृतीय	1,500	अष्टम	1,500
चतुर्थ	1,500	नवम	1,500
पंचम	1,500	दशम	1,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकन के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 360 नव वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रमाण अनुसार पौधों के लिए राशि 46,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,200 रुपये, खाद के लिए राशि 2,840 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,440 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,75,720 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **गैर माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र की भीतर 180 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष होने के कारण एवं 60 वर्गमीटर क्षेत्र को इलेक्ट्रिक पोल होने के कारण गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्लारी प्लान में किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम-तुलनात्मक, पहली-तीसरी के सारकारी भूमि में वृक्षारोपण या मिश्रित गार्डन (स्तुत के किनारे/मुक्तिधाम के किनारे/तालाब के किनारे) के लिए शासकीय भूमि का क्षेत्र और खसरा क्रमांक उपलब्ध बनाने संबंध में ग्राम पंचायत तुलनात्मक को आवेदन

किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के तहत पुनरावेषण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि की खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ 7.5 मीटर बाउंड्री छोड़ी गयी है, उस पर फेंसिंग कराकर पुनरावेषण का कार्य कराने तथा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की मस्टी एवं सीईआर के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मविध में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये किन्हा संरक्षण नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नम कुओं की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त कुओं की आवश्यकता पड़ने पर हाटई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के अंतर्गत किये जाने वाले पुनरावेषण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में साम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई सिमनी/किन्न स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं पत्ताई ऐश के उचित रख-रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कहकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार शून्य स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. ईट को पकाने के लिए ईट भट्टों में केवल जिम-जिम तकनीक या वर्टिकल शीफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से जिन-जिन स्वामी से पशुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्वामी पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सधन वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित पौधों संरखाईगत रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाधण्डी विल्टर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल या प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. जलसंग्रह आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संलग्नार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार वृक्षरोपण इसी मानसून में करते हुए पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोवाकफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लैंड सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनार्वित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से '1 किमी. की परिधि में अन्य कोई लैंड/ईट भट्टा संबंधित है अथवा नहीं?' के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें प्राप्त राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में यह विभिन्न वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करने।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
7. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल शिप या कोल माइन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, सूखी अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पैटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. उत्पादन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सूचकांकों अनुसार ईट भट्टों में स्थाई सुविधा (फोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईट भट्टों से निकलने वाले धाग का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. कच्चे माल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक बंद रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परिचोदना प्रसाधक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एसईएसी, छत्तीसगढ़ के एलेग्जा पत्र दिनांक 28/02/2025 के सम्मन से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(iv) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरीन्द कुमार खत्री, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित सारानुसार कुक्षारीयण इसी मानक में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक 202/खनि. -2 ख.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	60
01/04/2024 से 30/03/2024 तक	निरंक

3. कार्यालय वनसम्पदलाधिकारी, मुंगेली वनसम्पद जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक/स. वि./02/2024 मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 06 कि.मी. निकटतम वन्य जीव अभयारण्य (अधानकनार टाईगर रिजर्व) 07 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किराली 110 कि.मी. की दूरी पर है।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की दायि में अन्य कोई लौह/ईट भट्टों संघालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्दिष्ट किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसी न किये जाने की स्थिति में यह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनको द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृत्रिम अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे लकड़/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. उत्सर्जन के नियंत्रणों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सूचकांकों अनुसार ईट भट्टों में स्थाई सुक्ति (पोर्ट होल्स एवं फ्लैटफोर्म) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
10. ईट भट्टों से निकलने वाले धुआँ का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. कच्चे गाल/ईट परिवहन के दौरान गहनों को ढक कर रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कॉर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि के खसरा प्रमाण एवं खाता का उत्तरेख कसो हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. कलेक्टर एमिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्मित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसी न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनको द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृत्रिम अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे लकड़/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. वस्त्रार्जन के निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/समरेखा अनुसार ईट भट्टे में स्टाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईट भट्टे से निकलने वाले चूरा का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. कच्चे मातल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2025 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/07/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा मरली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई-

1. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	6.00	Following activities at Govt. Primary School Village-Tulsaghat	
			Water supply facility with maintenance including tiles in toilets of boys and girls	1.10
			Total	1.10

सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाचारक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 233/खनि. 02/2024-25 मुंगेली, दिनांक 17/03/2025 अनुसार आवेदित खदान से 01 किलोमीटर की पश्चि में 644 मीटर की दूरी पर 01 खदान अवस्थित है।
3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्रवाही मान्य होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. पर्यावरण स्वीकृति कार्यों के उत्प्रेक्षण का रोशनी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही हो, वह मान्य होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईनिंग से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटबॉल आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुपेरेड्स अनुसार ईट भट्टों में स्टाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं फ्लैटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. ईट भट्टों से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. कच्चे माल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-क्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम मंचायत के परामर्शकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रलोचनगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के परामर्शकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-क्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
11. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक 366/खनि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार जांचित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा जांचित खदान का क्षेत्रफल 2.31 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बंध, नई दिल्ली द्वारा सार्वेय पाण्डेय विस्व भारती सरकार पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक — मेसर्स ओजे डिवेल एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्री- श्री गतीन्द्र कुमार खत्री) को ग्राम-तुलसाघाट, तहसील-लोहरनी, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 61/1/3 में

स्थित मिट्टी (ग्रीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.31 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 घनमीटर (15,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संयुक्त 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स ओके ब्रिक्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्रो - श्री बलीन्द्र कुमार खत्री) को ग्राम-दुलसाघाट, तहसील-सोरमी, जिला-मुंगेरी के खसरा क्रमांक 61/1/3 में स्थित मिट्टी (ग्रीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.31 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 घनमीटर (15,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया-

1. ईट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्वोच की जानकारी (जैसे बालासोर, के-बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करें कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।)
2. वृक्षारोपण का रख-रखाव निर्धारित योजना के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संकलतादर 90 प्रतिशत हो।
3. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में निषिद्ध वैधानिक एवं दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स (प्रो - श्री विनय केशरवानी), ग्राम-जमुनाही, तहसील-सोरमी, जिला-मुंगेरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2380)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425146/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संभावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जमुनाही, तहसील-सोरमी, जिला-मुंगेरी स्थित खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए.सी. घल्लोसगढ़ के अधिन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 23/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय केशरवानी प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (ग्रीण खनिज) खदान, खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर

प्रतिषेध हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निधि-वायिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Marking) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (छनि शाखा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक / 349/खति-2 ज.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	वर्षवार	कुल उत्खनन (घ.मी.)
1	06/04/2018 से 31/03/2019 तक	580
2	01/04/2019 से 31/03/2020 तक	820
3	01/04/2020 से 31/03/2021 तक	980
4	01/04/2021 से 31/03/2022 तक	672
5	01/04/2022 से 31/03/2023 तक	768

दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अधिसूचना जानकारी छनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीमंदार का दिनांक 22/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - गवारी प्लान अर्थात् विषय गवारी कलेक्टर प्लान एण्ड इन्फार्मरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-संचालक (छनि प्रशासन), वास्ते कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटगंज के आपन क्रमांक

1107/खलि/लीन-1/2017 बलीदासजार दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 351/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूची निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 350/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघाट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं। नदी खदान से 80 मीटर एवं स्कूल 120 मीटर दूर है।
6. लीज का विवरण- लीज मेसर्स कोशरवानी बिरा प्रो.- श्री विनय कोशरवानी के नाम पर है। लीज की 30 वर्षों अवधि दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5 एवं 63/6 श्री विनय कुमारे के नाम पर तथा खसरा क्रमांक 47/4 श्रीमती जानकी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमंडलधिकारी, मुंगेली वनमंडल, जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/राजस्व/613 मुंगेली, दिनांक 07/03/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-लोहरी 7 कि.मी., स्कूल ग्राम-लोहरी 7 कि.मी. एवं अस्पताल लोहरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। सनिवारी नदी 100 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिब्रालीनिकल रिजर्व 28,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 23,374 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा एट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 643 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेच की लंबाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर विस्फी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पत्ताई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की समाप्तित जायु 23.37 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में गंधु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village- Jamunahi	
			Pavitra Van	7.90
			Nirman	
			Total	7.90

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलताश, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 405 नम पौधों के लिए राशि 80,780 रुपये, चोसिंग के लिए राशि 45,300 रुपये, खाद के लिए राशि 3,030 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,45,110 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,45,116 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम जमुनाही की हासकीय भूमि सस्तरा क्रमांक 50 के 40 हेक्टेयर तकका भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जामाकारी जिमोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में संश्लिष्ट करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं समाप्त से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवंटित क्षेत्र में स्थित 16 नम वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उसका वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई रक्षक प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवंटित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में घास/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई विमनी/किल्ला स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जायेगी।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले काँक्रेट एवं गत्ताई एस के उचित रख-रखाव के लिये दिन रीड का उपयोग किया जाएगा।
25. ईट को पकाने के लिए ईट भट्टों में कंबल जिन-जैंग तकनीक या बॉरिकल हॉपट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



(साखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये बिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान से ननिचारी नदी 80 मीटर दूर है। नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाए। अतः ननिचारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र स्थले हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. एक लाख ईट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्दिष्ट किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसी न किये जाने की स्थिति में वह विविध वैज्ञानिक एवं दृष्ट्यात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उत्तरदायक का बोझ भरे जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
7. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृत्रिम अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा वास्तविक अपशिष्ट जैसे लंगर/एसिस्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. उत्खनन के निगरानी के लिए संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/संपरिखा अनुसार ईट भट्टे में स्थाई सुईया (गैट होल्स एवं फोटोमैत्री) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. कच्चे मात/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एन.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु की दिनांक कोशरखानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान बाहरी जोड़क काफ़ी लगे जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

नमिति द्वारा साक्षम्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय सड़क, रेलगाड़ी, अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत जानकारी संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल मीटर परी मीटर स्थापित कर लीन बुक को नॉटेन किया जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामें, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्दिष्ट किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसी न किये जाने की स्थिति में वह विविधत विधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनको द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा। इसे आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, बैटरीज आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्सर्जन के नियंत्रणों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/समरथा अनुसार ईट भट्टों में स्वयं सुविधा (पोर्ट होल्स एवं स्लेटवॉर्मे) का निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईट भट्टों से निकलने वाले राख का उपयोग इन्हीं परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. कच्चे माल/ईट/कोयला/प्लाईवुड परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं प्लाई वुड के उचित रख-रखाव के लिए टिन शीट का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. आवेदित खदान में विद्यमान विभिन्न किल्ले को जिंग-जैंग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

Source: *U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts*.

100

8. कच्चे माल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को डंक कर रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कौयारे एवं फटाई ऐश के लक्षित रख-रखाव के लिए टिन शीट का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. आवेदित खदान में विद्यमान विभिन्न किन्ना को जिन-जंग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. समिति का मत है कि वीईआर एवं कूशाकरण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का प्रतीकगढ़ कपाकरण संस्कार सम्बल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही वीईआर एवं कूशाकरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
14. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुनेली के शासन क्रमांक 351/खनि-02/2023 मुनेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। गाननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल वेध नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्ष पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आवेदों में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मेसर्स कोशरावानी हिम्स (प्रो- श्री विनाय कोशरावानी) को ग्राम-जगुनाही, तहसील-लोहनी, जिला-मुनेली के खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6 में स्थित मिटटी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 17/11/2026 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स कोशरावानी हिम्स (प्रो- श्री

विनय कंशखानी), ग्राम-जमुनाही, तहसील-सीरमी, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 48/2, 48/3, 48/5, 47/4 एवं 63/8 में स्थित मिट्टी (पीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई 10,00,000 वर्ग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

1. ईट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले पत्ताई ऐश का स्कोत की जानकारी जैसे चालान, वे-बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करें कि पत्ताई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।
2. वृक्षारोपण का रख-रखाव निर्धारित योजना के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतापूर्वक 90 प्रतिशत हो।
3. समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

11. मेसर्स सिरखोला ऋषार स्टोन क्वारी (जी- बीमली मंदकांता मिश्र), ग्राम-सिरखोला, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2559)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/435453/2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट से संबंधित पत्थर (पीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सिरखोला, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,045.2 टन (15,402 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए.सी. मनेंद्रगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 495वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्र अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-15,402 घनमीटर (40,045.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला पर्यावरण सभाघर निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष समीत 09/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"IA, Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधीखुला के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतीबोधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार कूड़ापोषण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-जिरमिरी-भरतपुर के आप्रम क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.सी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	408.00
2019-20	1020.00
2020-21	268.00
2021-22	25.00
2022-23	26.00

समिति का मत है कि वर्ष 2022-23 के उपरोक्त खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घौटी का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) घौटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलान विध क्वारी क्लोजर प्लान किंग इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला- कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जाबक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाइज्ड क्वारी प्लान के कवरेज सेंटर (जाबक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-जिरमिरी-भरतपुर के आप्रम क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023

एन.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर मीटर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-विट्ठमिरी-सरसपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एन.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, सरपट, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज भीमटी संदर्भता भिन्न के नाम पर है। लीज बीड 18 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/03/2007 से 19/02/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज बीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 25/03/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2005/1529, दिनांक 29/09/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान को.एम.एल. से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र से वन भूमि की दूरी 620 मीटर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय ग्राम-सिरखोला 400 मीटर, स्कूल सिरखोला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 39 कि.मी. दूर है। ब्नास नदी 5 कि.मी., नहर 2 कि.मी. एवं बटदीन नाला 350 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिओलॉजिकल रिजर्व 8,73,188 टन, गार्डनेबल रिजर्व 4,81,611 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,15,450 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है। जोपल कास्ट सेमी मेकानाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर (7.5 मीटर डिपलॉय एवं 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में जामरी मिट्टी/ओक्स्बर्कन की मोटाई 0.5 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक ड्रमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्तरिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	95,014.20	सप्तम	30,083.60
द्वितीय	38,000.00	अन्तम	38,109.20

तृतीय	38,046.80	अष्टम	39,156.00
चतुर्थ	39,062.40	नवम	39,327.60
पंचम	39,078.00	दशम	40,045.20

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्ण से संभावित खदान की दुर्गन्धकर मिश्र (खसरा क्रमांक 121, क्षेत्रफल – 1.3) एवं परियोजना प्रस्तावक (श्रीमती चंदकांता मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में समुचित रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में पौधों का रोपण, कीमिन, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र (सखड़ी भूमि) के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः पौध उपरोक्त निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. **वास्तविक है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय** नई दिल्ली द्वारा नील कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (d) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से बाधा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
20	2%	0.4	Following activities at Village- Chanti	
			Pavitra Van	2.9875
			Total	2.9875

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, जामुन, करंज, सीसू, बौहार, सीताफल, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 475 नम पीछों के लिए राशि 23,750 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 50,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 25,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,38,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,50,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत मीटिंग के सहमति उपरंत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 136, क्षेत्रफल 0.18 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. संघारित खदान राज्यमार्ग से 38 मीटर दूर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माइनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया सयपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) कोटीयाप्त सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2022-23 के उपरंत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. पक्षर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. अनुमोदित रिहाईज्ड क्लारी प्लान के क्लेरिफ लेटर (जायका क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. संघारित खदान राज्यमार्ग से 38 मीटर दूर है। राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माइनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. कूपरी मिट्टी/ओकरचर्डन की जांच एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित सासकीय भूमि में पीछों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण

नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा क्लेयरिंग आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत संसालक, संसालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म्म इत्यादी बनाने तथा चयपुर अदल नगर, जिला - चयपुर (अतीसगड) को लेख किया जाए।

10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना थावे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संसालक, संसालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु अतीसगड पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया चयपुर अदल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
11. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार क्षति का उपयोग कर्त्ता हुए क्लेयरिंग किया जाएगा। सेमित पीसों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव कर्त्ता हुए म्यूनलम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की क्षति का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति को समाप्त प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही कार्य किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. स्वास्टिन का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करायें जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. अतीसगड आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से एमुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाजम्प्ट्री मिल्लर्स द्वारा सीमाबर्न का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसने विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।

20. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत अंशरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। इस बाबत अंशरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्धतानुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की एजेण्डा धन दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 06/03/2025 को रखा गया है।

(ए) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकाृ प्रतिनिधि उपस्थित हूँ। समिति द्वारा नवीं प्रस्ताव ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति पाई गई—

- परिचोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अग्रगत है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस में रजिस्ट्रार दिनांक 06/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिश निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिड़मिरी-मस्तापुर के ज्ञापन क्रमांक 674/खनि-2/2024-25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/06/2024 अनुसार वर्ष 2022-23 के बाद खदान में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
- पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम मेखला (ग्राम सभा) बांटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक 09/03/2011 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
- मॉडिफाईड क्वार्टी प्लान एलाम विद्य कक्षी बलौन्दर प्लान विद्य इन्डोसोर्मेट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिड़मिरी-मस्तापुर के ज्ञापन क्रमांक 483/ खनिज/उत्ख.सो.अनु./2024-25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/06/2024 द्वारा अनुमोदित है।
- संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलाजिकल रिजर्व 5,65,070 टन, माईनेबल रिजर्व 1,39,223 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,25,301 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2931.88 वर्गमीटर है। खदान की स्थापित आयु 05 वर्ष है। राज्यमार्ग से खदान की

न्यूनतम 100 मीटर की दूरी हेतु 6495.82 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर सड़किय क्षेत्र रखा गया है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,928.61
द्वितीय	40,045.30
तृतीय	24,069.91
चतुर्थ	12,721.13
पंचम	12,721.13

- उपरी मिट्टी/ओवरबर्डन की मात्रा 1,357.54 घनमीटर है, जिसे 7.5 मीटर की परिधि में भण्डारित किया जाना प्रस्तावित है।
- सीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सीज क्षेत्र की सीमा में धारा और 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.37 हेक्टेयर) पर 925 मम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 92,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये, बेंटिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रुपये तथा अन्य कार्य के लिए राशि 1,11,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,83,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,94,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- अवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पेड़ों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष की अन्दर सीईआर प्रोजेक्ट की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति को सफल प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही कार्य किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- प्लास्टिंग का कार्य बी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पशुजैविक डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत वाउण्ट्री मिल्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नही किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस आदेश से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकल्प लंबित नहीं है।
18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 06/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :-

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग, तन्मयजीव अभयारण्य तथा घोषित जीव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत जानकारी संबंधित वन विभाग से अनिवारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा बटरी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल से निर्मित मार्ग में डिजिटल चौंटर प्लो मीटर स्थापित कर लीज शुरू की मेन्टेन किये जाने बाबत राफथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

समानुसार एन.ई.ए.सी., जगदीसगढ़ के 584वें बैठक दिनांक 05/03/2025 को परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/08/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अद्यतनीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्योत्पन्न-वनमण्डलाधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला-मनेन्द्रगढ़, के ज्ञान का./त.ज./2025/1251 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 20/03/2025 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण 10 कि.मी. की दूरी में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर सिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 50 कि.मी. है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में विद्ये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण विद्ये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुसार कुल 2347.5 वर्गमीटर 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। चारों

उत्खानित क्षेत्र के पुनर्भरण हेतु बोल्टर 5618.75 घनमीटर ओवर बर्डन 2247.20 घनमीटर तथा समरी मिट्टी 1123.76 घनमीटर की आवश्यकता होगी। रैस्टोरेशन हेतु अनुमानित लागत राशि रुपये 3,56,000/- होगी।

3. जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल बीटर फ्लो मीटर स्थापित कर लोग बुक को मेन्टेन किया जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं कृषासोपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिंचाई पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषासोपन का कार्य पूर्ण किया जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति को सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर के आगम क्रमांक 118/खनिज/उम/2023 एन.सी.डी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंक, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जीरिजनाल एप्लिकेशन नं. 186 जॉक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने का कारण यह खदान थी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मैसर्स सिन्धुखोला ज्वार स्टोन क्वारी (प्रो- बीमती मंदकाता मिश्र) को ग्राम-सिन्धुखोला, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-चिहमिरी-भरतपुर) के खराब क्रमांक 140 में स्थित पत्थर (पीपल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, सन्तान-40.045 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुरोध की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को सम्पन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा का अमलौकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

1. समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के बिन्दु क्रमांक 2 में 'जारी पत्रावलीय स्वीकृति के तहत के अनुरूप तैयार हुए वृक्षारोपण (पीसी में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोकॉपी सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।' का उल्लेख है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं है कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार कितने नए वृक्षारोपण किए गए हैं।



- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल 2247.5 वर्गमीटर 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है।

उपरोक्त के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सौहार्दपूर्ण ढंग से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर पौधों में संख्यांक (Numbering) एवं पीछे के नाम का उत्प्रेषण किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी परियोजना प्रस्तावक से बनाया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थल को समीप पूर्व से संवर्धित खदान श्री दुर्गाशंकर मिश्रा (खसरा क्रमांक 121, क्षेत्रफल — 1.3) एवं शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य खेत में होने वाले घुल उत्खनन को रोकने के लिए है। अतः 7.5 मीटर या लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति होती है ना कि किसी अन्य क्षेत्र में करने से। अतः परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र के चारों तरफ में संयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
- उक्त पर्यवर्धित क्षेत्र को स्वीकृत योजना के अनुसार पुर्नभरण एवं उस पर वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- वृक्षारोपण एवं पुर्नभरण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जाये अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा शर्तों का उत्तरदायित्व पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार पत्र लेख किया जाए।

- मेसर्स मरखोही कृशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री दुर्गाशंकर मिश्रा), ग्राम-मरखोही, तहसील-मरतापुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-मरतापुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2558)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435370/2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवर्धित फल्लर (पीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मरखोही, तहसील-मरतापुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-मरतापुर) विधत खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन समता-23,314.2 टन प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का व्यवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टर, समता-8987 घनमीटर (23.3142 टन) जलियाँ हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोटिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 05/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 05/01/2023 तक वैध थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-बिरमिरी-भरतपुर से आपन क्रमांक 117/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.सी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	478
2019-20	712
2020-21	451
2021-22	30
2022-23	25

समिति का मत है कि वर्ष 2022-23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं अस्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत जमुना का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण

यह प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परिवर्धन प्रस्ताव द्वारा पथर उत्खनन एवं अपार के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) अनुमति की आवश्यकता विवरण दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – कचरी प्लान एलांग विध कचरी कलेक्टर प्लान विध इन्वारिमेंट मनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित कचरी प्लान में जाचक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित निम्नलिखित कचरी प्लान के कवरिंग लेटर (जाचक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूच्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी. दिनांक 13/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनोकेट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज भी दुर्गा शंकर मिश्रा के नाम पर है। लीज खंड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/02/2013 से 19/02/2018 तक की अवधि हेतु केय थी। तत्पश्चात् लीज खंड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के वृ. आपन क्रमांक/ग.वि./2005/451 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/03/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-मरखोही 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-मरखोही 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बनास नदी 3.5 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – प्रियालक्षिकल रिजर्व 4,87,679 टन, माईनेबल रिजर्व 3,64,818 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,28,336 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,778 वर्गमीटर है। आपन कार्ट सेमी मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (8 मीटर डिपलीक रण

सतर्फा से 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवरबैंक की मोटाई 0.5 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क़त्तार स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 943 वर्गमीटर है। ज़ेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल इन्स्ट्रिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रवृत्तन नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,776.4	षष्ठम	16,380.0
द्वितीय	13,501.8	सप्तम	17,791.8
तृतीय	14,040.0	अष्टम	20,565.0
चतुर्थ	14,898.0	नवम	21,309.6
पंचम	15,600.0	दशम	23,314.2

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का सभापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित खदान के समीप पूर्व से संभावित खदान बीमाती चंद्रकांता मिश्रा (खतरा क्रमांक 140, क्षेत्रफल-2) एवं परियोजना प्रस्तावक (श्री दुर्गाशंकर मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 मम पीछे का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खतरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,776 वर्गमीटर है, जिसमें से सतही भूमि से 333 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। समिति द्वारा पाया गया कि चूना का उत्खनन अनुमोदित क्वारी प्लान में नहीं किया गया है। अतः लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उत्खनन करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव सम्पदा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही चूना उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नोन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना के लागत में क़ाबू स्थापना की शक्ति सम्मिलित नहीं है। अतः समिति का मत है कि परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाना आवश्यक है। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, धर्मशरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रायपुर जटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का मालूम प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2022-23 के उपरोक्त खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. पथर उत्खनन एवं क़ाबू के संभालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. अनुमोदित रिवाइज्ड क़ाबू प्लान के कन्वर्गिंग लेटर (जबकि क़ाबू एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. सीज क्षेत्र के शर्तों और 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए अद्यतन स्थिति में क़ाबू की गणना संशोधित अनुमोदित क़ाबू प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. सीज क्षेत्र के शर्तों और 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे-अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
10. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 नग पीछी का रोपण, फंसिंग, खाद एवं सिंकाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क़ाबू, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाए। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाए।

- g

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(38) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खननानुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेंड्या एच दिनांक 28/03/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकृत मेमोरेण्डम दिनांक 06/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षावरण (पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-नरसपुर के ह्रासन क्रमांक 676/ख.लि.-2/2024-25 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 06/08/2024 अनुसार वर्ष 2022-23 के बाद ह्रासन में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
4. पत्थर उत्खनन एवं कचरा के संचालन हेतु राम गंदायत (राम समा) जन्मा की कार्यवाही निवर्ण, दिनांक 23/11/2009 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
5. अनुमोदित रिजर्वेशन पवारी प्लान खनि अधिकारी, जिला- कोरिया के ह्रासन क्रमांक 1720/खनिज/खलि2/2016 कोरिया, बैतुण्डपुर दिनांक 09/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के उत्तर पूर्वी दिशा में उत्खनित क्षेत्र रुकबा 333 वर्गमीटर पूर्व से था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक

इसका उक्त परस्मिन् क्षेत्र का पुनर्भरण कर लिया गया है। अतः रिजर्व की गणना में संशोधन की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है।

7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किन्हीं गहरे चस्त्रनिर्त क्षेत्र का पुनर्भरण कर लिया गया है। अतः रेस्टोरेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।
8. निकटतम आवादी ग्राम-मरखोही 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-हरखोहा 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 16 कि.मी. दूर है। बनास नदी 3 कि.मी. दूर स्थित है।
9. कागरी मिट्टी की मात्रा 2,967.5 घनमीटर है जिससे लीज क्षेत्र 7.5 सीमा पट्टी में सम्भारित किया जाएगा।
10. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.38 हेक्टेयर) पर 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 95,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये, फौसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,86,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,36,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना तामत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Village-Markhoi	
			Pavitra van	7.495
			Total	7.495

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम-मरखोही के जाससीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 525 नग पीछी के लिए राशि 52,500 रुपये, खाद के लिए राशि 20,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये, फौसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,08,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,70,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,79,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जमुवा (आशित ग्राम मरखोही) के सहमति उपरान्त मध्याह्न स्थान (खसत क्रमांक 122 क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर) के संघ में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. आवेदित संस्थान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। संश्लिष्ट पीछी का 5 वर्ष तक वृक्षित देखभाल व रख-रखाव करते हुए

न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. पर्यावरणीय सदैव्यता प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सीईआर प्रोजेक्ट की राशि का प्रस्तावित कदम में संपादन करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गए प्रोजेक्ट में ही खर्च किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. इररिगेशन का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. उत्तीरागढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इन्स्ट फलसार्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सन्निध नियमों के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, खासाब, नदी, भाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटवी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित नहीं है।
21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तात्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि जाहोदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिन 17/11/2025 को संगणन 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा का अंगीकार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया है कि समिति की 554वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के बिन्दु क्रमांक 2 में "घाटी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पीछी में संख्यांकन Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।" का उल्लेख है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार कितने नए वृक्षारोपण किये गये हैं। अतः प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी परियोजना प्रस्तावक से मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थल की समीप पूर्व से संयोजित खदान बीनटी चंदकांठा मिश्रा (खसरा क्रमांक 140, क्षेत्रफल-2) एवं शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य स्त्रोत में होने वाले धूल वस्त्राजन को रोकने के लिए है। अतः 7.5 मीटर या लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति होती है ना कि किसी अन्य क्षेत्र में करने से। अतः परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र के बाहरी सरफ में उपयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,778 वर्गमीटर है, जिसमें से सतही भूमि से 333 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को स्वीकृत योजना के अनुसार पुर्नभरण एवं उस पर वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
4. वृक्षारोपण एवं पुर्नभरण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जाने अन्यथा प्रत्तीतमय पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
5. वृक्षारोपण का रख-रखाव निर्धारित योजना के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतापूर्वक 90 प्रतिशत हो।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार पत्र लेख किया जाए

13. मैसर्स कशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री हरकेश तिवारी), ग्राम-डोमगापाड़ा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2158)

ऑनलाईन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400731/2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से आपन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी दिनांक 21/10/2022 (मकनीकी सचिवी होने के

कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित पत्थर (गीण खनिज) खदान है। ग्राम-डोमनापाड़ा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-विस्तर्गिरी-भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक - 525, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-17,004 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की कुल मुरारी तिथारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर क़रार (कोलेचईट संस्कारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-8,540 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण संस्थागत निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। इस संस्था में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संकाय में श्री मोरख कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती बाई क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया द्वारा "श्री हरकोश तिथारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शाली का उत्खनन करने बाबा।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पारस के सार्वजनिक भूमि पर अवैध स्लाबिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध स्लाबिंग कामभूतन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार को क़रार पर स्लाबिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बांस एवं स्लाबिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका बंधन तनक क़रार के विजस्टी सिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनारपति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क़रार का संघालन अनारपार जारी है।
5. CGR नद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने से जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
6. सीक जांच पर खदान एवं क़रार क्षेत्र में रखे गए खनिज का मित्राज दस्तावेज अनुसार नहीं है।

7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई राश्वन्ती से अधिक उत्खनन किया गया है।
8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिछी किया जा चुका है।
9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्पत्ति अनुसार खदान क्षेत्र के परिसर में साढ़े सात (7.5) मीटर की घाड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बिछा जा चुका है।
10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
11. खदान क्षेत्र में अमिटों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।
12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।

समिति द्वारा संलग्न सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिक्षावत पत्र में उल्लेखित हिन्दुओं की जीव बचालक, समाजनालय, भौमिनी तथा खनिजार्थ, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर जटल नगर, जिला - रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी / जीव प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कारेक्टर (खनिज सञ्चय, जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर) को सूचित किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 17/01/2023 को नज्दम से शिकायत पत्र में उल्लेखित विन्दुओं की जाँच हेतु संघातक, संघातमालय, भीमिही तथा खनिकर्म, इंदोवती भवन, मया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 02/02/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसम्पु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/12/2023 को जानकारी/तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024

शमिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में चलनविधित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जीब संभालक, संभालनालय, मौमिखी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, महा रायपुर जटल नगर, जिला - रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यवत्मक जानकारी/ जीब प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में माननीय एनजीटी के ओ.ए. क्रमांक 117 ऑफ 2023, दिनांक 12/07/2023 द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार E. Action Takes Report के बिन्दु क्रमांक 1 में "The report of the Revenue Department and Mining Department did not find any encroachment and illegal mining beyond the lease area in other two stone quarry's i.e. M/s Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha Village Hastinapur) and M/s Hrushesh Tiwari (Khasra No. 16, area 2.0 Ha Village Hastinapur)".

- समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक जी पूर्ण में चाही गई व्यक्तिगत जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

(स) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिणोजन प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध मात्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

g

30/05/2012 को जारी अन्तर्गत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी की दूरी पर है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-डोमनावाड़ा 1.0 कि.मी. स्कूल ग्राम-डोमनावाड़ा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-सरोला 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 100 मीटर एवं राज्यमार्ग 170 मीटर दूर है। इससे नदी 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है। सैनहारी निर्जल फारेस्ट 3 कि.मी. एवं इससे निर्जल फारेस्ट 4 कि.मी. दूर है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिथोली/जिथल रिजर्व 3,25,581 टन, मार्बल/मरल रिजर्व 1,60,837 टन एवं निकल/निकल रिजर्व 1,52,799 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,900 वर्गमीटर है। खनन कार्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर (7 मीटर हिललॉक एवं 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जेक ड्रैगर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,065	षष्ठम	15,990
द्वितीय	13,650	सप्तम	16,263
तृतीय	14,235	अष्टम	16,536
चतुर्थ	14,820	नवम	16,809
पंचम	15,405	दशम	17,004

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर से माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत भालौर का अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 50 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है पीछो की संख्या में वृद्धि कर वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित पीछो का रोपण, फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 6 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण निम्न प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. गैर माईनिंग क्षेत्र - 336 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at Govt. Primary School Village- Khutapara	
			Rain water harvesting	0.65
			Potable drinking water facility	0.30
			Running water facility for toilet	0.15
			Plantation in school	0.15
			Total	1.25

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए कुशांगण किया जाएगा। चैमित मीनों का 3 वर्ष तक उचित देखभाल में रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिती के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. ब्लास्टिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत डिस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. छल्लासगढ़ जादरों पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पट्टाजिटिंग डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, खासा, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस संधि से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित नहीं है।
26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 06/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. शिकायत पत्र में उल्लेखित विन्युओं की जीव संरक्षण, संरक्षणालय, भीमिनी तथा खनिज, इलायती मय, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कटायी जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी / जीव प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. विकासगत पत्र में उल्लेखित हिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्त, इदावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर से कनाये जाने एवं सम्बन्धित जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्त, इदावती भवन, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी वर्षावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानचुन में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2021 के उपरांत किए गए वनखनन की वार्षिक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी संबंधित जानकारी संबंधित वन विभाग से अनामतित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी/ओवरलैन्ड की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, कीटन, छाया एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 6 वर्षों का वार्षिक व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

			Village-Khutapara	
			Intalation of Rain water Harvesting	0.85
			Potable Drinking Water Facility	0.35
			Running water facility for toilets	0.15
			Plantation in School & Health Center Premises	0.15
			Total	1.25

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रिन्सिपल (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 800 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 80,000 रुपये, फेंसिंग एवं रख-रखाव के लिए राशि 50,000 रुपये, स्थापना के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंचाई आदि के लिए राशि 1,21,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,59,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 4,40,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसंगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्य) जिला-कोरिया-बैकुण्ठपुर की तारीख क्रमांक/438/खनिज/उ.प./2022 कोरिया-बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 खदान, कुल क्षेत्रफल-1.0 हेक्टेयर है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) ने दिनांक 13/09/2018 की पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स कशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री हरकेश तिवारी) को ग्राम-डोमनापारा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-भरतपुर) के ससरा क्रमांक 525 में स्थित पत्थर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-17,004 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 21वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुमति या स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स कशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री हरकेश तिवारी) को ग्राम-डोमनापारा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-भरतपुर) के ससरा क्रमांक 525 में स्थित पत्थर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-17,004 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे की नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं न्यायात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

14. मेसर्स श्री ज्वालामुखी स्टोन क्वारर (प्रो.- श्री कमलेश कुमार गुप्ता), ग्राम-सिंगरोली, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2545)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुसूचा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 433314 / 2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सिंगरोली, तहसील-महतपुर, जिला-कोरिया खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल-3.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-68,679 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माँहित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 24/08/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/08/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/08/2024 को सी. बी.पी. मोहरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिधारी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष को सी.पी. मोहरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदनुसार छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/08/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचारणीय था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुतीकरण के दौरान समस्त दस्तावेज एवं जानकारी प्रस्तुत की गई थी। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/02/2025 को अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार मुन्हा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल-3.9 हेक्टेयर, क्षमता-26,415 घनमीटर (68,679 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समारोह निर्धारण प्रधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक

27/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2025 तक की अवधि हेतु वैध है।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित क्राफ्टनुसार पुस्तारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 88/खनिज/उ.प./2023 एन.वी.सी. दिनांक 02/06/2023 द्वारा विमत वर्ग में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	1.360
2019-20	3.428
2020-21	2.618
2021-22	0.389
2022-23	4.155

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं कचरा के संबंध में ग्राम पंचायत सिंगरीली का दिनांक 26/06/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - कचरी प्लान एलांग विथ कचरी जमाखत प्लान विथ इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के आपन क्र. 1048/खनिज/स्था/2015/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/08/2015 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 89 ए/खनिज/उ.प./2023 एन.वी.सी. दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर के आपन क्रमांक 99/खनिज/उ.प./2023 एन.वी.सी. दिनांक 02/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार समस्त खदान से 200 मीटर की परिधि में ये सार्वजनिक संरचनाएं जैसे नदी, बांध, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज डीड संबंधी विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज मैसर्स श्री ज्वालामुखी स्टोन कचरा (प्रो.- श्री कमलेश कुमार गुप्ता) के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अवधि दिनांक 20/01/2017 से 19/01/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला-मनेन्द्रगढ़ के आपन क्रमांक/सा.वि./2014/1407 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 09/07/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र

कन क्षेत्र की सीमा से 370 मीटर की दूरी पर है। आवेदित स्थल पर पेड़ की संख्या 1 है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय ग्राम-सिंघरीली 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-हरचौका 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। बनाव नदी 5 कि.मी. दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड इरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिवाजीजिफान रिजर्व 12,16,800 टन, माईनेबल रिजर्व 10,60,254 टन एवं रिकॉनबल रिजर्व 9,54,228 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई (हिलरीक) 6 मीटर है। हिलरीक होने के कारण ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। सर्वेक्षर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,223.80	षष्ठम	52,644.80
द्वितीय	37,284.00	सप्तम	56,992.00
तृतीय	30,815.10	अष्टम	61,058.40
चतुर्थ	43,017.00	नवम	65,590.20
पंचम	49,575.50	दशम	68,879.00

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,625 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 1,82,500 रुपये, खाद के लिए राशि 85,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रुपये, फेंसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 80,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 25,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,67,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,95,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षा वर्षात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Village-Singroli	
			Pavitra van Nirman	4.56
			Total	4.56

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम-सिंगरोली के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 वर्ग फीट के लिए राशि 1,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 65,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रुपये, फेंसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 25,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,90,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,68,000 रुपये हेतु धटकदार जय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिंगरोली को सहमति उपरान्त व्यापारिक स्थान (खसरा क्रमांक 781, क्षेत्रफल 4.27 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. परियोजना से संबंधित शपथ पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम्पिटिव डस्ट चल्सार्जन् नियंत्रण, सफ़ा वृक्षारोपण एवं 40 प्रतिशत जीवन सार सुनिश्चित, जी.जी. एम.एस. द्वारा कंट्रोल स्टाफिंग, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित साख्य से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं सार्वजन आदि सबंध शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिसरधन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलचपन का प्रकरण लंबित नहीं है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जाएगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय सड़क, जन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत जानकारी, संरक्षित वन विभाग से अनामतित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

गठानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के 884वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/06/2025 को ज्ञानकारी/चर्चासत्र प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की छठावीं बैठक दिनांक 23/07/2025

कमिटी द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यवाहक वनमण्डलालीकाशी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला-मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्र./त.म./2025/1298 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 20/03/2025 से जारी जनावृत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण 10 कि.मी. की परिधि से स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 08 कि.मी. है।
2. समिति का मत है कि री-इंजार् एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही री-इंजार् एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से समाप्तित कराया जाना आवश्यक है।
3. कार्यवाहक फ्लेक्स्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-धरमिली-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99 ए/खनिज/उप/2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.9 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल वेब, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाम्देय दिल्ली भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जोरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

2. समिति का मत है कि सीईआर एवं वृक्षारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रखरीय प्रशासन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने में सहायता मिले त्रि-पक्षीय समिति से संस्थापित करना जाना आवश्यक है।

3. कार्यवाहक कमिश्नर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-भिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99 ए/खनिज/रूप/2023 एम.बी.सी. दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.9 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल वेब, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र चाम्पेय विरुद्ध भारत सरकार, धर्मोतरन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जोरिजेशन एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/06/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मेसर्स श्री ज्वालामुखी स्टोन इण्डर (प्रो.- श्री कमलेश कुमार गुप्ता) की घान-सिंगवाली, तहसील-भरतपुर जिला-काठिया की खाना क्रमांक 801 में स्थित

2. आवेदनक - मेरसरी मी ज्वालामुखी स्टोन इण्डर (प्रो.- श्री कमलेश कुमार गुप्ता) की काम-सिंगरौली, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया की खनन इलाक 801 में स्थित

1

दिनांक वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाइन आवेदन	ई.सी. - 440208 एवं 18/08/2023 ई.सी.एस. जारी दिनांक - 13/08/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक - 21/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (ग्रीन खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.152 हेक्टेयर एवं 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 911, 915 श्रीमती सरला पांडे खसरा क्रमांक 891, 892, 919 श्री बंशीलाल पांडे खसरा क्रमांक 892, 894, 920, 918 - श्री कोमल प्रसाद पांडे (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 16/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री बंशीलाल पांडे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - मिट्टी (ग्रीन खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 क्षेत्रफल - 2.152 हेक्टेयर क्षमता - 2,200 घनमीटर/वर्ष दिनांक - 31/01/2018	सी.ई.आई.ए.ए. जिला-बिलासपुर पर्यावरणीय रीतिरिती की वेबसाइट दिनांक 22/02/2038 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का मालन प्रतिवेदन	रव-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित सतानुरात वृक्षरोपण 250 मग किया गया है।
दिगत वर्षों में किये गये उत्खनन	कार्यालय कॉलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है:- वर्ष 2018-19 में 2,200 घनमीटर वर्ष 2019-20 में 2,083 घनमीटर वर्ष 2020-21 में 2,018 घनमीटर वर्ष 2021-22 में 2,180 घनमीटर वर्ष 2022-23 में 2,198 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बलसडीहरी दिनांक 18/10/2007	ग्राम पंचायत का अद्यतन अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना

	10 वर्ष हेतु परित की गई थी।	आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/10/2017	
500 मीटर	दिनांक 04/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 04/08/2023	सकरी सड़क - 1.5 कि.मी. आबादी क्षेत्र - 1.5 कि.मी.
लीज डीथ	लीज धारक - श्री कौशल प्रसाद पांडे अवधि-23/02/2038 से 22/02/2038	
वन विभाग एन.ओ.सी.	कनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक - 10/10/2023	वन क्षेत्र से दूरी - 15.03 कि.मी. अंशानुसार टाईगर रिजर्व - 20.4 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - चनाडौंगरी 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम - चनाडौंगरी 1.5 कि.मी. अस्पताल - सकरी 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 3 कि.मी. राज्यमार्ग - 3.50 कि.मी.	घोंघा भागा - 70 मीटर नहर - 250 मीटर तालाब - 2.5 कि.मी. एमीकट - 2.0 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	6 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनकारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट मैनुअल सिस्टम - जियोमोर्फिकल 22,208 घनमीटर मार्बल 20,362 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 1.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 0.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 0.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी से शोध सामग्री हेतु प्लाई ऐश का प्रतिशत - 40% एक लाख ईट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा - 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,100 घनमीटर तृतीय 2,200 घनमीटर चतुर्थ 2,200 घनमीटर पंचम 2,200 घनमीटर षष्ठम 2,095 घनमीटर सप्तम 1,810 घनमीटर अष्टम 1,765 घनमीटर नवम 1,690 घनमीटर दशम 1,550 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल - 825 वर्गमीटर	परखनित - नहीं।
लीज क्षेत्र की भीतर भट्ठा स्थापित	हॉ. क्षेत्रफल - 3,418 वर्गमीटर फिक्स सिमनी की न्यूनतम ऊंचाई - 33 मीटर	
जल आपूर्ति	माधा - 7 घनमीटर स्त्रोत - ग्राम पंचायत	

पुष्कारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर की गहराई और पुष्कारोपण - 300 नग वर्तमान पुष्कारोपण - 250 नग क्षेत्र प्रस्तावित पुष्कारोपण - 50 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 1,12,000 रुपये
क्षेत्री	बी-2	आवधिक खदान का क्षेत्रफल 2.152 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा संलग्न सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत का आद्यतन अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (सीपीआर) प्रस्तुत किया जाए।
3. ईट निर्माण हेतु जिग-जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा फट्टी में क्षेत्र 50 नग पौधों का निर्देशानुसार पुष्कारोपण कर (फट्टी में संख्याकरण (Numbering) एवं नाम) फोटोप्राप्त सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार की पर्यावरण, जल एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किया जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया जाए।
6. प्रतीकमय आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन पुष्कारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सार्वसुखी रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. क्यूजिटिव डेस्ट कार्रवाई के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. के तहत तब की गई शक्ति का उपयोग गांव के द्वारा सी.ई.ई. भूमि में पॉसिंग करके पुष्कारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. ईट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत प्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



12. ईट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबा राधकृष्ण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबा राधकृष्ण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राधकृष्ण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई एक्स्प्लेन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तथानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी. पी. मोन्हेरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. मोन्हेरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को अलगत करवाया गया। तदोपरान्त छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 18/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु दिवालयीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बंशी लाल पांडे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पार्श्व गई:-

1. उत्खनन के संबंध में काम पेशागत घनाडोगरी का दिनांक 06/10/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment	Percentage of Capital	Amount Required	Amount Proposed & Details for CER Activities
--------------------	-----------------------	-----------------	--

8. न्यूनिटिव ड्राफ्ट उत्तराज्ञेन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रयास प्राकृतिक जल, खेतों, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत/स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर जियरिंग फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. ईट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. ईट निर्माण से निकलने वाले सिजेक्ट डिपस का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव एवं बंद निर्माण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/संयोजन से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पंचायत, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराज्ञेन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पिगत वर्ष 2023-24 के उत्पादन आंकड़े की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल में रेन वाटर हार्वैस्टिंग का समायोजन करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत संबंधित संस्थानों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. उत्तीरगढ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/03/2025 एवं 13/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के जापन क्रमांक/2580/ख.लि./म.क्र./2025, बिलासपुर दिनांक 08/03/2025 द्वारा द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (घनमीटर में)
2023-2024	1,620
2024-2025	1,332

2. सी.ई.आर. को ताबत प्रस्तावित स्कूल में रैन वाटर हायैस्टिंग का समायोजन करते हुये संगठित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37	2%	0.74	Following activities	
			Rain Water Harvesting Structure Construction work in Chanadongri Govt. High School	0.00
			Running Water Facility for Toilet in Chanadongri Govt. High School	0.15
			Plantation in Govt. Primary School & Govt. High School	0.15
			Total	0.90

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय पूर्ण मा. शाला के परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 3,000 रुपये, टी-गाई के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, बिचाई के लिए राशि 500 रुपये तथा रख-रखाव एवं अन्य कार्य के लिए राशि 1,500 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. के सहित उपर्युक्त कार्यों हेतु राज. पंचायत बनावडीपट्टी का अनुपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, राज. पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), के ज्ञापन दिनांक 04/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.152 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.पी.टी. प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाम्देय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अनिज्जन्त एपिलीकेशन नं. 188 जीक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक — मेसर्स चनाडोंगरी प्रिन्स अर्थ कार्परी (प्री.— श्री कोमल प्रसाद पांडे) को ग्राम—चनाडोंगरी, तहसील—तखतपुर, जिला—बिलासपुर के खसरा क्रमांक 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 में स्थित मिट्टी (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—2.152 हेक्टेयर, क्षमता—2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का जफ़्तौकरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स चनाडोंगरी प्रिन्स अर्थ कार्परी (प्री.— श्री कोमल प्रसाद पांडे) को ग्राम—चनाडोंगरी, तहसील—तखतपुर, जिला—बिलासपुर के खसरा क्रमांक 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 में स्थित मिट्टी (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—2.152 हेक्टेयर, क्षमता—2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।
2. ईट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्रोत की जानकारी जैसे घालान, से-ग्रिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करें कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।
3. वृक्षारोपण का रख-रखाव निश्चित योजना के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संकलतादर 80 प्रतिशत हो।
4. प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माइनिंग प्लान अनुसार 40 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाने का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 प्रतिशत उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवाद बनाने हेतु मिट्टी के साथ फ्लाई ऐश की मात्रा 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है। अतः कितना प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग किया जाएगा इस संबंध में जानकारी शपथ पत्र की साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभिन्न वैधानिक एवं दम्भालयक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के निर्णय के शिर्षु क्रमांक 2 एवं 4 की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. मेसर्स कुहेली ब्रिक्स अर्थ ब्ले स्वारी एण्ड फिक्स विमनी प्लांट (प्रो.-बीनती प्रेमवती साहू), ग्राम-कुहेली, ठाहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1883)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 248674/2021, दिनांक 23/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से जापन दिनांक 24/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कुहेली, ठाहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 744, 750/1, 750/4, 750/1 एवं 750/2, कुल क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक कुमार राठीर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष बताया गया कि जानकारी अधूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 21/12/2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/01/2024 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / संस्थापन सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 22/05/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/06/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक कुमार राठीर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में चाही पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में मिट्टी खसरा क्रमांक 744, 750/1, 750/4, 750/1 एवं 750/2, कुल क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर, क्षमता-1,200 घनमीटर (8,00,000 मग) प्रतिवर्ष

हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाबाट निर्धारण अधिकार कोरिया द्वारा दिनांक 17/10/2017 को जारी की गई थी। जिसकी वैधता 5 वर्ष तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"BA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17/10/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 289 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 789/खनिज/स.ए./मिट्टी/2023 कोरिया दिनांक 09/02/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	0.00 (मू-प्रवेश की अनुमति अग्रप्राप्त होने के कारण उत्पादन नहीं किया गया)
2019	670.00
2020	145.00
2021	589.00
2022 दिसम्बर तक	114.00

समिति का मत है कि दिसम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन को संघ ने ग्राम पंचायत कुंडेली का दिनांक 04/12/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - कपरी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक 3180/खनिज/2017 सुरजपुर, दिनांक 13/09/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 789/खनिज/स.ए./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की सूची निम्न है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 789/खनिज/चम./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनोकर एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं सीज का विवरण - भूमि एवं सीज सीमाती प्रमासती साधू (आवेदन) के नाम पर है। सीज चौक 30 वर्ग अर्थात् दिनांक 21/12/2017 से 24/12/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक/तक.क./1343 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी 1 कि.मी. है। आवेदित खदान से निकटतम नेशनल पार्क / अभ्यारण्य की दूरी 10 कि.मी. है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कुडेली 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। कोरिण्डाखो नदी 6 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 22,320 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 19,548 घनमीटर एवं रिक्वरेबल रिजर्व 18,576 है। सीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर है। आपन कार्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। सीज क्षेत्र के भीतर 1,000 वर्गमीटर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत चूनाई एंश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिकनाय किया जाता है। अनुमोदित त्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 49 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल साउथव्हाट वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – सीज क्षेत्र की सीमा में बाहों ओर 1 मीटर की पट्टी में 289 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि सीज क्षेत्र के बाहों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीछी का रोपण, सुखा हेतु पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at Village-Kudeli	
			Pavitra Van	2.98
			Nirman	
			Total	2.98

15. सीईआर के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आवला, मक, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पीछी के लिए राशि 4,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 40,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 86,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,03,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुडेली के सहमति उपरांत ब्यागोन्च स्थान (खसरा क्रमांक 1042 क्षेत्रफल 7.04 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर में) के संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. माईनिंग सीज क्षेत्र के अंदर साधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सन्वाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सीज क्षेत्र के 1 मीटर में प्रपोजल के अनुसार वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. सीईआर के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. छत्तीसगढ़ जायदाद पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से कम्युनिटिव ड्रस्ट उत्सारित होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, खाद्य, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लड़ित नहीं है।
23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. भारत सरकार को जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस नोटीसेडम में दिए गए बिन्दुवार जानकारी का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. दिसम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अधोलन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर को-डाईनेट के अनुसार बाउण्ड्री पिलर्स लगाये जाए तथा लीज क्षेत्र की सीमा पर तार फेंसिंग कर पालन प्रतिवेदन कोटेशनस सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा घट्टी में बुझारोपण हेतु पीछी का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का भटकावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित फिक्स्ड विननी की लंबाई की गणना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. ईट निर्माण हेतु आवश्यक कोयले के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. कोयले का सुरक्षित रखने के लिए षीड का निर्माण करने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. विद्यमान विननी किलन को 2 वर्ष के भीतर जन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन कर जिन-जिन पद्धति का उपयोग करते हुये ईट निर्माण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के शासन दिनांक 03/10/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/01/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श संपन्नत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मल्ली का खकलौकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- प्रतिक्रिया के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी प्राप्त होने के संपात ही परियोजना प्रस्तावक की पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

- प्रस्ताव का विवरण** — यह पूर्व से संघालित पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—चित्तमोर, तहसील—बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया (वर्तमान में तहसील—मनेन्द्रगढ़, जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल—0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—3201 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एचईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 13/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अधूरी होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं सम्बन्धित सुरंगगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एचईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.एस. परमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- L पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल—5.48 हेक्टेयर, क्षमता—1,231 घनमीटर (3,201 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रधिकरण, कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलधाम परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

“9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.”

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/03/2023 तक वैध थी।

- L परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एचईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1412 दिनांक 13/08/2023 द्वारा “Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion.” के संघ में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलधाम परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित

किया गया था, इस परिधि में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

- iii. निर्धारित सत्रानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के आपन क्रमांक 18/खनिज/उ.पो.अनु./2023 एम.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	माईनिंग प्लान में प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर)	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)
2017-18	968	निरंक
2018-19	1,074	निरंक
2019-20	1,159	200
2020-21	1,168	80
2021-22	1,189	40
2022-23	1,192	निरंक

2. नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं कचरा की स्थापना में संबंध में नगर पालिक निगम, चिरमिरी का दिनांक 15/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - कचारी प्लान एरान विथ ग्वाली कलेक्टर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-मरसपुर के पृ. आपन क्रमांक/20/खनिज/उ.पो.अनु./2023 एम.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के आपन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अनधिकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के आपन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, मूल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्राधिकृत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री लक्ष्मण कुमार चतुर्वेदी के नाम पर है। लीज डीठ 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/06/2012 से 24/06/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीठ 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/06/2017 से 24/06/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के आपन क्रमांक /मा.वि./783 बैकुण्ठपुर, दिनांक

15/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 04 कि.मी. की दूरी पर है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। समिति का मत है कि खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. परिसिध्दिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलधारण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, परिसिध्दिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 70,200 टन, माईनेबल रिजर्व 29,004 टन एवं रिक्वेस्टेबल रिजर्व 26,103 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,826 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सोमी मैकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में कंकर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैक ईमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्क्वैडिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,619.4	षष्ठम	3,100.5
द्वितीय	2,792.4	सप्तम	3,198
तृतीय	3,014.7	अष्टम	3,201.9
चतुर्थ	3,038.1	नवम	2,542.8
पंचम	3,092.7	दशम	2,472.0

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इन बावत् सेंट्रल घाघण्डा नौटल अर्बाबिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, कीर्सिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्ताव जमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चित्तझोर में एक भी तालाब नहीं होने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पीछा रोपण का कार्य किये जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि आपके द्वारा ही पूर्व में ग्राम चित्तझोर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण संग्राह्य जाना आवश्यक है। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पीछा का रोपण, बीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (खसरा जमाका, क्षेत्रफल) संग्राह्य जाना तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. आशयित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार शशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पीछा का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 60 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की शशि का प्रस्तावित कार्य में जगमोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. ब्लास्टिंग का कार्य बी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से प्रयुजिटिव असट उत्खनन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत माछण्ट्री पिल्सर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसका संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इन खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से स्थापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिशुचना का.जो. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरादेश का प्रकरण लंबित नहीं है।



13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में ग्राम चितझोर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में ग्राम चितझोर में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, पौंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का संटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (जिसमें क्रमांक, क्षेत्रफल) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के सम्मेलन प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही खर्च किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

संदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की आपन दिनांक 27/06/2024 के परिप्रेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/09/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में सी.ई.आर. के प्रस्ताव में त्रुटिग्रस्त ग्राम चितझोर के तालाब का उल्लेख हो गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं होगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार सशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.48	Following activities at, Govt. High Sec. School Village-Chitjhor	
			Plantation around	2.764

			School Campus	
			Total	2.704

सी.ई.आर. के अंतर्गत "वृक्षारोपण" के तहत (मीन, आम, अर्जुन, सौरभ, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीछों के लिए राशि 2,000 रुपये, टि-गोड के लिए राशि 20,000 रुपये, खार के लिए राशि 2,200 रुपये, सिंचाई के लिए 12,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 72,200 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,98,200 रुपये हेतु परतकनाह व्यवसाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपरराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- कार्यालय कालेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के आदेश क्रमांक 21/खनिज/च.प./2023 एन.सी.बी. दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। सार्वजनिक एन.सी.टी. प्रिंसिपल बेध, नई दिल्ली द्वारा सतर्क पाप्केय विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिकल्पन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एपिलिकेशन नं. 180 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- आवेदक - मेसर्स वित्तश्री कछर स्टोन क्वारी (प्रो - श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी) को ग्राम-वित्तश्री, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) के खसरा क्रमांक 137/1 में स्थित पथर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर, क्षमता-3,201 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 17/11/2025 की संख्या 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चित्तझोर ग्रो-स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी) को ग्राम-चित्तझोर, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में तहसील-मनेन्दगढ़, जिला-मनेन्दगढ़-चिरनेरी-भरतपुर) के खसरा क्रमांक 137/1 में स्थित पत्थर (गीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर, क्षमता-3201 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर डिमेंटिंग (Demarcation) फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वृक्षारोपण का रख-रखाव निर्धारित योजना के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सकलतादर 80 प्रतिशत हो।
4. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की विधिति में विविध कानूनी एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

18. मेसर्स डेतका आईनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती ममता अडवाल), ग्राम-कैतवल, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2396)

ऑनलाइन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/437323/2023, दिनांक 27/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कैतवल, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1757, कुल क्षेत्रफल-0.68 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

सर्वेक्षण सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2016 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., जलौसगढ़ के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** — ऊपरी प्लान अनुसार जियोलीजिकल रिजर्व 78,728 टन (30,279 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 33,383 टन (12,832 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 30,038 टन (11,548 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलीजिकल रिजर्व 68557 टन (28,368 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 23,194 टन (8,829 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 20,874 टन (8,028 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी लीना पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,665 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल गांजा 5,275.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,101 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (नाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर सूक्ष्मोपयोग के लिए एवं शेष 4,174.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 194/2, क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर) में संचयनित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जोश हैमर से डिजिटल एवं कंट्रोल प्लानिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में खान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में गांजा प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्पन्न (₹)	वर्ष	प्रस्तावित उत्पन्न (₹)
प्रथम	2,388.8	षष्ठम	3,393
द्वितीय	2,472.6	सातम	3,541.2
तृतीय	2,670.2	आठम	3,900
चतुर्थ	2,827.5	नवम	4,282.2
पंचम	3,118.1	दशम	4,761.9

- Q

है। साथ ही उक्त एलखनिह क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु विस्तृत रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a)(ii) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. गैर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वार्टी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माइनिंग क्षेत्र रखे जाने बाबत स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Village- Ketha	
			Plantation around village Pond	0.50
			Total	0.50

18. सीईआर के अंतर्गत तालाब के घाटी और (ग्राम की विभिन्न प्रजातियाँ, फलदार एवं जामुन) 25 नम वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 2,500 रुपये, कोरिंग के लिए राशि 3,750 रुपये, खाद के लिए राशि 1,250 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रुपये, अन्य कार्यों हेतु 5,000 रुपये प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रुपये हेतु घटकवार धन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कंतका के सहमति उपरोक्त वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 1424, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक सम्भरित किये जाने, रोप ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में नकारित किये जाने। इस प्रकार सम्भरित ऊपरी मिट्टी का किसी भी

प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस गिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनको निरीक्षण/भरण के दौरान निरीक्षण कराया जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियमित मगदण्डी को अनुसार डी.जी.एन.एच. अधिकृत एवं पंजीकृत प्लास्टिक विशेषज्ञ के द्वारा ही स्थापित कराया जाएगा।
21. प्रयुजितिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. सतीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा खदान के संयोजन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे :-

- i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जायेगा।
- ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न परेशु अवशेषों के निपटान के लिए सेंट्रिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
- iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेंट्रलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जायेगा।
- iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार स्थानीयों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- v. खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सभ्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
- vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सभ्य वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.55 कि.मी. तथा नहर 9.35 कि.मी. की दूरी पर है जो कि सतीसगढ़ गीण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक

दूरियों से अधिक है। अतः खदान संघातन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (j) (अ) के पालन से सावधान एवं नहर पर प्रभाव को रोकना जा सकेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलचलन का प्रकरण लंबित नहीं है।
28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.95 कि.मी., अस्पताल 8.5 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1.2 कि.मी. की दूरी पर है जो कि उत्तीर्णगढ़ गाँव खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—
 - i. खदान की माईन बाउन्ड्री में घासी और सघन वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. इनारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जाएगा, जिससे रास्ते में धड़न से खनिज ना गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा।
 - vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत कार्य किया जाएगा।
 - vii. सड़कों को उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुकात हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
 - viii. धूल एवं क्वैस्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड फ्लेस्टर्स द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की

- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- [illegible]



क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर का नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/12/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1466/खनिज/उ.प./2023-24 सुरजपुर दिनांक 22/02/2024 के अनुसार दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निरंक है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सुरजपुर वनमण्डल जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्र./ग.वि./7771 सुरजपुर दिनांक 14/11/2024 से जारी अभावलि प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 260 मीटर दूर है एवं समीर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी 80 कि.मी. है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की बाउंड्री के खुदे हुए 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 2 मीटर गहरे गड्ढे को 400 घनमीटर मुक्कम व खरब पत्थर के द्वारा बैकफिल किया जाएगा, जिसके पुनर्भरण हेतु अनुमानित कुल लागत राशि रुपये 33,750/- होगी।
4. अनुमेदित जगह प्लान में उल्लेखित लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर पैर साईमिंग क्षेत्र को ऑफिस, अस्थाई स्टोरेज एवं लेबर कम हेतु उपयोग किया जाएगा। उक्त हेतु सप्प पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस नोमोरेशन में दिये गये निर्देश का किन्तुधान पालन किये जाने बाबत जानकारी एवं सप्प पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का मत है कि सीईओएर एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईओएर एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सुरजपुर दिनांक 16/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सत्यापन निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेक्टर नई दिल्ली द्वारा सार्वेड पारम्पेय विस्मृद् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिकल्पन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल

एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मेसर्स बेंतवा जाईनरी स्टोन कारी (प्रो.- श्रीमती ममता अग्रवाल) को ग्राम-बेंतवा, तहसील न जिला-सुरजपुर के वनस वार्डक 1757 में स्थित साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.68 हेक्टेयर क्षमता-4,781.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अंशोक्तन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया :-

1. पूर्व में डी.ई.आई.ए. जिला-सुरजपुर द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की काला समाप्त हो चुका है। प्राधिकरण का मत है कि आवेदित खदान को नये खदान के अनुसार पुन विचार कर प्रस्तुत करें। साथ ही पुनर्जनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? की समझ में लाभ उपरान्त अनुशंसा करें।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सुरजपुर वनमण्डल जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्र./मा. वि./777। सुरजपुर, दिनांक 14/11/2024 से जारी अनामत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर दूर है। गान्धीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनोच्च की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. से भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिशुचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्य को परीक्षण में परीक्षण उपरान्त उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.-1, छत्तीसगढ़ की समझ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी.-1, छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स बनकोम्बो ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.-श्री राकेश कुमार अग्रवाल), ग्राम-बनकोम्बो, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2883)

ऑनलाईन आवेदन-प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/सीजी/आईएनडी/464243/2023, दिनांक 04/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन एवं ईट उत्पादन (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बनकोम्बो, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर स्थित

खसरा क्रमांक 138/2, 139/1, 139/2, 140 एवं 148 कुल क्षेत्रफल-3.451 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,000 घनमीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 17/07/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 667 वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राकेश कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं आर.एम.पी. सी पी.डी. पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नतीजा, प्रस्तुत जानकारी का ज्वलांकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में मिट्टी उत्खनन एवं ईट उत्पादन खदान खसरा क्रमांक 138/2, 139/1, 139/2, 140 एवं 148 कुल क्षेत्रफल-3.451 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,000 घनमीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समझौते निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जसपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता लौक अवधि दिनांक 21/10/2039 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षांतोपन नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञापन दिनांक 26/07/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	माईनिंग प्लान में वार्षिक उत्पादन क्षमता (घ.मी. में)	DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्पादन क्षमता (घ.मी. में)	उत्पादन (घ.मी. में)
1	2017 - 2018	2,000	2,000 (10 लाख नग)	960
2	2018 - 2019	2,000	2,000 (10 लाख नग)	1,629
3	2019 - 2020	2,000	2,000 (10 लाख नग)	92
4	2020 - 2021	2,000	2,000 (10 लाख नग)	338
5	2021 - 2022	2,000	2,000 (10 लाख नग)	310
6	2022 - 2023	2,000	2,000 (10 लाख नग)	1,270
7	2023 - 2024	2,000	2,000 (10 लाख नग)	540
8	2024 - 2025	2,000	2,000 (10 लाख नग)	830

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनकोम्बो डा. दिनांक 05/09/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वारी प्लान ऑफ़ प्रिक्वैज अवधि माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3693/ख.लि.-2/2016 रायगढ़, दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (सामिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 717/ख.श./2023 जशपुर, दिनांक 27/11/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (सामिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 716/ख.श./2023 जशपुर, दिनांक 27/12/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। धामीज काष्ठा सड़क 135 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. लीज का विवरण — लीज श्री राजेश कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज की 05 वर्षों अवधि दिनांक 22/10/2009 से 21/10/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज की 25 वर्षों अवधि दिनांक 22/10/2014 से 21/10/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।
7. भू-स्वामित्व — भूमि खसरा क्रमांक 138/2 एवं 140 श्री चेतन, खसरा क्रमांक 139/1 श्री रुद्रेश्वर घाटव, खसरा क्रमांक 148 श्रीमती शोभा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 139/2 श्री राजेश अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2024/5388 जशपुर, दिनांक 08/10/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित भूमि से निकटतम वनक्षेत्र की दूरी 300 मीटर, निकटतम कन्याजीय अभ्यारण की दूरी 25 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 250 कि.मी. है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-बनकोम्बो 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम-बनकोम्बो 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल-कुनकुरी 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग-10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग-22.65 कि.मी. दूर है। ईश्वर नदी-650 मीटर, नासा-320 मीटर, तालाब-920 मीटर एवं नहर-1.30 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — क्वारी प्लान अनुसार जियोलाजिकल रिजर्व 69,020 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 69,653 घनमीटर एवं रिक्वरेबल रिजर्व 53,687 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलाजिकल रिजर्व 66,550 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 57,163 घनमीटर एवं रिक्वरेबल रिजर्व 51,217 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1 मीटर एवं सीढ़ाई 1 मीटर है।

लीज क्षेत्र की सीमा 1,700 वर्गमीटर क्षेत्र में ईट निर्माण हेतु मरदा स्थापित है जिसकी किक्स विमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। प्रस्तावित ईट का निर्माण में जिग-जैग (Zig-Zag) पद्धति का उपयोग किया जाएगा। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। प्रति 1,00,000 नग ईट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यक होती है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। सर्वेक्ष प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,000	षष्ठम	2,000
द्वितीय	2,000	सप्तम	2,000
तृतीय	2,000	आष्टम	2,000
चतुर्थ	2,000	नवम	2,000
दशम	2,000	दशम	2,000

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 09 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सोरपेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाधा सेन्ट्रल घासमण वाटर अथॉरिटी का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 1 मीटर की पट्टी में कुल 487 नग वृक्षारोपण किया जाना है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण एवं रख-रखाव के लिए प्रथम वर्ष हेतु राशि 5,05,945 रुपये तथा आगामी चार वर्षों हेतु राशि 10,28,980 रुपये (कुल राशि 15,34,925 रुपये) का घटकवार विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है, जिसमें से पिट क्षेत्र 422 वर्गमीटर, 1 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। खुदी हुई सुरक्षा बाकंडी का पिट क्षेत्र को लगभग 644 घनमीटर मिट्टी एवं पलाई ऐश से 45 डिग्री स्लोप बनाते हुये बैकफील किया जावेगा, इसके साथ ही बाकंडी के स्लोप को सजवूती प्रदान करते हुये 422 घनमीटर पत्थर का उपयोग करके बाकंडी स्लोप में 0.50 मीटर मोटा विवित किया जावेगा। पुन:मरण हेतु अनुमानित कुल लागत राशि 1,25,500/- रुपये होगी।
16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** - लीज क्षेत्र में विमनी विधात होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 1,700 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा समर्पता निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

54	2%	1.08	Following activities at Govt. Middle School Village- Bonkombo	
			Installation of 1KW Solar System	1.10
			Total	1.10

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष में सीज क्षेत्र में विद्यमान किनरी किले को आवश्यक परिवर्तन करवा कर जिग-जैग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ईट निर्माण किया जाएगा। साथ ही जानकारी छ. माह पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. ईट मटेर को जिगजैग टेक्नोलॉजी के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करवाने के पश्चात् ही ईट बनाने की प्रक्रिया शुरू किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. पर्यावरण स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. भविष्य में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किये बिना कोई भी उत्खनन कार्य एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई खसम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित क्षेत्र की उत्खनित भाग को पुनः बरत कर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा नाम एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ सहित छ. माह पालन प्रतिवेदन के साथ किया जाएगा।
24. आवेदित क्षेत्र के बाहर कोई भी उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, खान पंचायत के प्राधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्राधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराना जाना आवश्यक है।
26. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के दायन क्रमांक 717/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 27/11/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3454 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैठ. नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पावरफुल विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं.



188 औफ 2016 एवं अग) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मान्य होगी।
2. प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सहायक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने हेतु घातीयरूप पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. आवेदक - मेसर्स मेसर्स बगकोम्बो प्रिक्त ऊर्ध्व माईन (प्रो- श्री राजेश कुमार अग्रवाल) को घात-बगकोम्बो, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर के खसरा क्रमांक 138/2, 139/1, 139/2, 140 एवं 148 में स्थित निट्टी (गोण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल-3481 हेक्टेयर, क्षमता-2000 टन (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को सम्पन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण का रख-रखाव निर्धारित संयोजन के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलता दर 90 प्रतिशत हो।
3. रेस्टोरेशन प्लान अनुसार उत्खनित 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी को पुनर्भवन कर जियोटैग फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. ईट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले पत्ताई ऐश का स्त्रोत की जानकारी जैसे घातान, वे-बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करें कि पत्ताई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।
5. कार्यालय वनमन्त्रालयधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के डायन क्रमांक/मा.पि./2024/5385 जशपुर, दिनांक 08/10/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि से निकटतम वनक्षेत्र 300 मीटर दूरी पर स्थित है। मन्त्रीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी

निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दूरी का आदेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण पर पुनर्विचार किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण पर आगामी कार्यवाही किया जाएगा।

20. मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मोहन सिंह कश्यप), ग्राम-बालेंगा, तहसील व जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2601)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एलआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 438124/2023, दिनांक 26/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नूना पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बालेंगा, तहसील व जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129, कुल क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-50.000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एलआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंह कश्यप, प्रॉपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन को संबंध में ग्राम पंचायत बालेंगा का दिनांक 29/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान विथ रिक्त जॉक माइनिंग फॉर फास्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी बलेंजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 485/खनिज/उत्खनन/2021-22 दतेवाड़ा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के पु. ज्ञापन क्रमांक 045/खनिज/खलि. 3/16/2020-21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 22/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.832 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के पु. ज्ञापन क्रमांक 1014/खनिज/खलि. 4/16/2020-21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, बाँदर पुल, नदी, अस्पताल, स्कूल, एमीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.जी.आई. संशुद्धी विवरण** – एल.जी.आई. श्री मोहन सिंह कश्यप के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1369/खनिज/खलि.4/18/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संघालक, संघालनालय भूमिकी तथा खनिकम् नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3438/खनि 02/उ.प.-अनु.निष्ठा./न.क.50/2017(3) नया रायपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा एल.जी.आई. में वैधता वृद्धि बाबत पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (प्रार्थित दिनांक 12/06/2023) हेतु वैध है। तदोपरान्त एल.जी.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संघालक, भूमिकी तथा खनिकम् नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 34/2023 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 08/06/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ मीन खनिज निगम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज कीड जारी किया गया है।** समिति का मत है कि पूर्व में आवेदित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संचालित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **भू-स्वामित्व** – भूमि रासरा क्रमांक 1142 श्री रूपसिंग व स्व. श्रीमती सुखी, खसरा क्रमांक 1138/2 श्री मक्तु व पयमा, खसरा क्रमांक 1129 श्री लखन, खसरा क्रमांक 1138 तथा 1141 श्री बीनाथ, खसरा क्रमांक 1140 श्री लखेश्वर एवं खसरा क्रमांक 1138/1 व 1138/1 श्री क्यू पार्वती, गिता, भुमिका एवं लेखिका के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन संप्रदायधिकारी, वनसंग्रह बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र./कटा.ज./1860 जगदलपुर, दिनांक 12/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1 कि.मी. दूर है।
11. **सहस्रपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बालेभा 300 मीटर, स्कूल बस्तर 8.3 कि.मी. एवं अस्पताल बस्तर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 880 मीटर दूर है। मारखण्डी नदी 1.25 कि.मी. दूर स्थित है।
12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलाजिकल रिजर्व 8,67,683 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,70,153 टन है। लीज की 7.6 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,013.2 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट

सेमी कंक्रीटाईज्ड विधि में उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गांज 0.160 घनमीटर है, जिसमें से 2.478 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फेंकाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 4.882 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 1211) में संरक्षित कर मण्डरावित किया जाएगा। खेद की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की समावित आयु 18.8 वर्ष है। जैक रैनर से ड्रिलिंग एवं ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में कचरा प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	17,500
चतुर्थ	25,000
पंचम	50,000

14. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,181 मनुष्य वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 88,236 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,80,300 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,28,700 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,58,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,53,236 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,42,744 रुपये हेतु घटकवार भाव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल से देखने पर लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय सौकरिता की शर्तों का उल्लंघन है। अतः लीज उपरत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःसाव किये जाने बाबत रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे नीचे माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। अर्त क्रमांक 1/11/11 के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall

be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”

उक्त मानक चर्च के अनुसार माईनिंग क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेम्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विस्तार से बर्बाद करवात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at Village- Balenga	
			Pavitra Van Niman	12.60
			Total	12.60

19. सीईआर के अंतर्गत “पवित्र वन निर्माण” के तहत (आवला, बीपल, नीम, आम, जर्जुन, जामुन, अमलतारा, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 नम पैथी के लिए राशि 38,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 42,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,58,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,39,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,21,000 रुपये हेतु परतकरवात व्यव वां विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम पंचायत बालेंगा के सहमति करवात पंचायतस्थ स्थान (खसरा क्रमांक 1108, क्षेत्रफल 2.21 हेक्टेयर में से 0.2 हेक्टेयर) को संरक्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूई में आवेदित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संयोजित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्तरनिष्ठ क्षेत्र को माईनिंग प्लान में समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरनिष्ठ क्षेत्र को पुनःसमाप्त हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत राफय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से पबुजिटिव इस्ट रासायन होना, इन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत राफय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र की माइनिंग प्लान में सम्मवेश कर सशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के संघ में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पूर्व से उत्खनित है, जिसका उत्खनन कच्ची प्लान किंग स्किन ऑफ माइनिंग फोर कास्ट फाईव ईयर एम्ब कच्ची क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनर्भरण हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार खोदे गए हिस्से में भरी जाने वाली भूल की मात्रा 4,128.62 घनमीटर है, सुस्था अवरोध क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपशिष्ट और बर्देन की आवश्यकता होगी और वृक्षारोपण कार्य के लिए अवरोध क्षेत्र में फैलाने के लिए 860.13 घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसके ऊपर उत्खनित क्षेत्र में लगभग 175 पीछे लगाए जाएंगे। मिट्टी का उपयोग केवल 7.5 मीटर सुस्था अवरोध में केवल ऊपरी परत में 1.00 मीटर मोटाई तक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा, न कि पूरे भरने के काम के लिए। लीज क्षेत्र के बाहर मौजूद पुराने गड्ढों के लिए अवरोध में भरने की इतान को नियमानुसार बनाए रखा जाएगा और मिट्टी के कटाव और ढलान की स्थिरता बनाए रखने के लिए सीडिंग के साथ कोवर मैटिंग की जाएगी, जिसका कुल लागत लगभग 3,10,000 रुपये होगा।

7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनर्भरण हेतु रेस्टोरेशन प्लान के उपरल (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 175 नग पीछों के लिए राशि 10,500 रुपये, खाद के लिए राशि 5,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 14,500 रुपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरल निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.00	Following activities at Village- Balanga	
			Pavitra Van Nirman	13.742
			Total	13.742

5. सीईआर के अंतर्गत 'पवित्र वन निर्माण' के तहत (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पीछों के लिए राशि 64,340 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,70,840 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 10,03,456 रुपये हेतु धटानवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज पंचायत बालंगा के समक्ष उपरल

प्रदायीय स्थान (घनता 1135, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

6. समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है, परंतु परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र पूर्व-से-उत्खनित है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र में उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया है एवं उत्खनित क्षेत्र के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? के संबंध में धनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।
7. ब्लॉकिंग का कार्य बी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत डिस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कतारों जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्लुइडिंग इन्स्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. गाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं सीमित पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउन्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, ताताब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, मध्यप्रदेश, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई सल्लेषण का प्रकरण लंबित नहीं है।
13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना चाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक की उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्यापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिश निर्देशों का पालन किया जाएगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र को उपचाली उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा नुसारोपन आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत संचालक, संचालनालय, मौमिकी तथा खनिकर्मी, इंदौर की मयान, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अकेल उत्खनन किया जाना चाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, मौमिकी तथा खनिकर्मी को एवं पर्यावरण की अति धुनसाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त बांछित जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025:

समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जगदलपुर, जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 1331/खनिज/ख.लि.1/16/2020-21/ब.प. जगदलपुर दिनांक 19/08/2025 के प्रतिवेदन अनुसार उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का दिनांक 18/08/2025 को निरीक्षण किया गया जिसमें आर्सेनल क्षेत्र ने कुछ खुले मोल्दूर

है एवं उत्तर-पश्चिम भाग में पूर्व में उत्खनित गद्दा स्थित है जो कि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार खसरा क्रमांक 1142 एकड़ कुल रकबा 0.88 हेक्टेयर में से 0.88 हेक्टेयर निजी भूमि क्षेत्र पर दिनांक 21/05/2001 से 20/05/2013 तक 10 वर्ष हेतु भीमती सहिता नेताम जगदलपुर के पत्र में उत्खनितपट्टा स्वीकृत था जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है तथा सामवासीधों ने बताया कि खदान कंद होने के परभावत प्राचीणों द्वारा निजी निर्माण कार्य हेतु उक्त क्षेत्र से बाल्टर निकालकर उपयोग किया गया है। उक्त खसरा क्रमांक 1142 आवेदक की निजी भूमि है जिले अन्य खसरों के समाहित कर आवेदक द्वारा नवीन खदान स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। का उल्लेख है।

2. सीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदित खदान को नवीन एल.ओ.आई. जारी की गई है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्पत्ति की प्रती की आवश्यकता नहीं है।
4. एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 428, दिनांक 20/05/2025 को माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र को उपचार्यी उपायों (Remedial Measures) के संक्षेप में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने संबंध संचालक, संचालनालय, भीमिती तथा स्थानिक, इधवाही मयन, नया रायपुर अटल नगर जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।
5. एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 428, दिनांक 20/05/2025 प्रतिबोधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिती तथा स्थानिक, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।
6. एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 430, दिनांक 20/05/2025 प्रतिबोधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पर्यावरण को क्षति पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्जात नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का मालन

किया जावेगा इस बाबत कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 09/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत राफा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या खेतीसंगठन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण के कार्य पूर्ण किये जाने को उपर्युक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
12. माननीय एन.सी.टी. प्रिंसिपल बीच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पावरकेब विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जॉरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श तत्पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. आपन क्रमांक 345/खनिज/खलि.3/16/2020-21/उप. जगदलपुर, दिनांक 22/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, संयोजित 2, 832 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान-बालेगा) का क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जगदलपुर, जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 1331/खनिज/खलि.1/16/2020-21/उप. जगदलपुर, दिनांक 19/06/2023 को जानकारी प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन के कुछ भाग में वृक्षान्धन पाये जाने पर नियमानुसार आगामी 06 माह में कार्यवाही पूर्ण कर एच.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ को अवगत कराने तथा इस शर्त को संचालन सम्मति में जोड़े जाने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है। इस संस्था में संचालक, संचालनालय, भूमि की तथा खनिकों को एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाय।
3. मेसर्स बालेगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मोहन सिंह करण) की राग-बालेगा, तहसील व जिला-बस्तर के खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129 में स्थित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कल

क्षेत्रफल-1.98 हेक्टेयर क्षमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संयुक्त 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मरली का अपलोड किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुये आवेदक - मैसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो. - श्री मोहन सिंह कश्यप) को ग्राम-बालेंगा, तहसील व जिला-बस्तर के खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1129/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129 में स्थित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.98 हेक्टेयर क्षमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी को पुनर्भरण हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार खोदे गए हिस्से में भरी जाने वाली घूल की मात्रा 4,128.62 घनमीटर है, सुरक्षा अवरोध क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपेक्षित ओवर बर्डन की आवश्यकता होगी और वृक्षारोपण कार्य के लिए अवरोध क्षेत्र में कटान के लिए 880.13 घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसके ऊपर उपस्थित क्षेत्र में लगभग 175 पौधे लगाए जाएंगे। मिट्टी का उपयोग केवल 7.5 मीटर सुरक्षा अवरोध में केवल ऊपरी परत में 1.00 मीटर मोटाई तक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा, न कि पूरे भरने के काम के लिए। लीज क्षेत्र को बाहर भीजूद घुसने पड़ने के लिए अवरोध में भरने की इतनी की नियमानुसार बनाए रखा जाएगा और मिट्टी के कटाव और इतनी की विधरता बनाए रखने के लिए सीडिंग की साथ कोयर मैटिंग की जाएगी। रेस्टोरेशन प्लान के अनुसार पुनर्भरण का कार्य एवं वृक्षारोपण (1181 मग) का कार्य 01 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाए। पुनर्भरण एवं वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जाये अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का पालन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी सम्मिलित है।
- समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विविध वैधानिक एवं दण्डजन्य कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

21. मैसर्स श्री कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड (कायदेकदर-श्री दिनेश कुमार गौयल), ग्राम-विरेनदनगर, तहसील-दाङ्गफनगर, जिला-बलरामपुर-छमानुजगंज (सचिवालय का मरली क्रमांक 2594)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी - 437308 एवं 21/07/2023	
खदान का प्रकार	सजावन पत्थर (गीण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.52 हेक्टेयर एवं 54,828.33 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	893	
नू-स्वामित्व	निजी भूमि श्रीमती निशा सिंह	सहमति पत्र प्राप्त

बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री हरद कुमार आचार्य अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी	ग्राम पंचायत विरेन्द्रनगर दिनांक 05/10/2021	सखनन एवं क़सर के संबंध में
सखनन योजना अनुमोदन	दिनांक 30/06/2023	
500 मीटर	जानि निरीक्षक, जिला-बलरामपुर-रामानुजमंजु द्वारा जारी पत्र दिनांक 30/05/2023 अन्य खदानों की संख्या- निरंक	आवृत्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिला-बलरामपुर-रामानुजमंजु के जाचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
200 मीटर	प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, सरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिला-बलरामपुर-रामानुजमंजु के जाचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. कारक - मेसर्स सी कुदरगड़ी स्टोन क़सर प्राइवेट लिमिटेड दिनांक - 04/05/2023 क़ैदा अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर द्वारा जारी दिनांक 31/03/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 3 कि.मी
गहत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी- विरेन्द्र नगर 400 मीटर स्कूल- ग्राम-गौदला 2.8 कि.मी. अस्पताल- सुलमुखी 3.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग- 43 कि.मी. राज्यमार्ग -465 कि.मी.	झरिया नाला - 2 कि.मी. मौसमी नाला- 500 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीपुलैटेड एरिया पारिस्थितिकीय	

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जाचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, संरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जाचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपर की मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की फट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीछी, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत "परिचित वन निर्माण" के लिए (जंगल, बड़े पीपल, नीम आम, अर्जुन, बेल आदि) वन मंत्रालय के सहमति पत्रों पर व्यवस्थित स्थान (खतराकार विवरण एवं होनहार सहित) में वृक्षारोपण हेतु पीछी, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपर की मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्स्थापन में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. लाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. स्लास्लिट का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत डिस्कोर्टक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पसुजिटिंग डस्ट उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउन्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंशबद्धीकरण (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंशबद्धीकरण (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रत्यर्पण का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/06/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंशबद्धीकरण (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 (2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंशबद्धीकरण (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

संपरीक्षा संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सद्वानुसार एस.ई.ए.सी. छातीसंगठन के आयोजन दिनांक 08/02/2024 के परिपेक्ष्य में परिचर्चाओं/प्रस्तावों द्वारा दिनांक 09/05/2024 की उभयपक्षी/प्रस्तावों प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024

समिति द्वारा नकी, प्रस्तुत जानकारी का उपयोग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. खनि निरीक्षक का दिनांक 30/05/2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक बताई गई है। आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जालक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जालक क्रमांक 226/खनिज/जाखनि/2024 बलरामपुर दिनांक 29/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनिकट बंध, राज्यमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
3. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षावेषण किये जाने हेतु उपशोध किया जाएगा।
4. जल की आपूर्ति से जल के माध्यम से की जाएगी। इस मामले में नोटल साधन की ओर अर्थोसिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य संपन्न पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में वृक्षारोपण (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 1,05,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 45,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रुपये, तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,28,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,54,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Village- Virendra Nagar	
			Pavitra Van Neman	9.58
			Total	9.58

सीईआर के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 70,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 30,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रुपये, तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,78,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,80,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत विरेन्द्र नगर के सहनति उपरंत संधारण स्थान (खसत क्रमांक 1278, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विनाश न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वास में किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सधन वृक्षारोपण किये जाने एवं सीमित पौधों का संरखाईयल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. ब्लास्टिंग का कार्य जी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. छत्तीसगढ़ जादशी पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों की रोजगार दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से प्रयुजितिव वस्तु उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल विश्लेषण की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री प्लानिंग द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संस्थापन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.ता. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/06/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानाझानों के संकेत में प्रमाण पत्र कार्यालय बल्लेकटन (खनिज साख्वा) जिला-बलरामपुर-समानुजगंज के ज़ाब्तक अभ्यांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आगेगी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2024 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षापूर्वक प्रस्तावक द्वारा चयन दिनांक 28/11/2024 के मध्यम से जानकारी/वस्तुनिष्ठ प्रस्तुत किया गया।

(स) सभिति की ४७२वीं बैठक दिनांक १९/०८/२०२५:

समिति द्वारा भरती, प्रस्तुत जानकारी का उपयोग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक / 1465 / खनिज / चल्खनि / 2024 बलरामपुर, दिनांक 25 / 11 / 2024 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता दिनांक 03 / 05 / 2024 को समाप्त हो गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भूमिहीन तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के



अपील प्रकरण क्रमांक 48/2024 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 28/05/2024 को प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत नियमानुसार प्रकरण में आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति हेतु उक्त पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने, उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

3. समिति का मत है कि सीईआर एवं पुनारोपण कार्य के शीमटिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं पुनारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. खनि निरीक्षक का दिनांक 30/05/2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न बताई गई है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेध, नई दिल्ली द्वारा सल्वेज पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एडिजेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक - मेसर्स सी कुंदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड (आयरेक्टर - श्री दिनेश कुमार मोघल) को ग्राम-विरेनदनगर, तहसील-साइफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 693 में स्थित साधारण परचर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.52 हेक्टेयर, क्षमता-54,928.33 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संवन् 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मरती का अप्रवीकृत किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स सी कुंदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड (आयरेक्टर - श्री दिनेश कुमार मोघल) को ग्राम-विरेनदनगर, तहसील-साइफनगर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 693 में स्थित

साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.52 हेक्टर, क्षमता-54,928.33 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा भित्ति बिछाये गये शॉर्ट का गालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दम्भानक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

22. मेसर्स गड्डीपलना रैनाईट माईन (प्रो.- श्री विमल सुनिया), ग्राम-गड्डीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोडगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2525)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433333/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित रैनाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गड्डीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोडगांव स्थित क्षमता क्रमांक 2/53, कुल क्षेत्रफल-1.416 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसकी पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 12.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण संगठन निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के सम्मेलन ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 18/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकुमार नाम, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में रैनाईट खदान क्षमता क्रमांक 2/53 कुल क्षेत्रफल-3.50 एकड़, क्षमता-1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संगठन निर्धारण

प्राधिकरण, जिला-कोम्हागांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2017 को जारी की गई।

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोम्हागांव के आपन क्रमांक 112/खनिज/2023-24 कोम्हागांव, दिनांक 23/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2018 से 31/03/2019	767.318
01/04/2019 से 31/03/2020	944.567
01/04/2020 से 31/03/2021	541.908
01/04/2021 से 31/03/2022	805.564
01/04/2022 से 31/03/2023	1,079.939
01/04/2023 से 31/07/2023	323.843

समिति का मत है कि दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा धारा गया कि पूर्व में डीईआईएए, छ.ग. द्वारा पैनआईट (ग्रीन खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पैनआईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उपर्युक्त संक्षेप में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संक्षेप में ग्राम पंचायत राष्ट्रीकरण का दिनांक 17/09/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - विध्वंस अधिक माईनिंग अर्लींग विध्वंस प्रोपेसियर्स गार्डन कंसिजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनिज शाखा), संचालनालय, भौतिकी तथा खनिज नया रायपुर अटल नगर के आपन क्रमांक 1590/एमसीसी/एमपी-04/2014, अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोम्हागांव के आपन क्रमांक 113/खनिज/2023-24 कोम्हागांव, दिनांक

23/08/2023 के अनुसार जामेदिल खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित खदानों की संख्या निम्न है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोम्हागांव के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/2023-24 कोम्हागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरफट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनोकेट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज की विमल दुनिया के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अवधि दिनांक 20/04/1993 से 22/04/1993 तक की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अवधि दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। समिति का मत है कि वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का लीज का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कोम्हागांव समान्य वन मण्डल जिला-कोम्हागांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./358 कोम्हागांव दिनांक 23/01/1998 द्वारा जारी पत्र अनुसार यह वन संस्थाप अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की कार्यात्मक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. मूल्यपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आमावी, स्कूल एवं अस्पताल धाम-करसगांव 1.73 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। बरकी नावा 2.23 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिओलॉजिकल रिजर्व 1,50,805 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 61,700 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,544 वर्गमीटर है। जॉपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में जोहर बडैन की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। बेस की कंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क़रार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल

गट्टीपालना की सहमति उपरांत पर्यावरण स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 0.250 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) कोटीपालना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए. ज.ग. द्वारा रेनोईट (लीज खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में रेनोईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उचित के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वस्तुविक माध्य की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वस्तुविक दूरी का चलेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की दूरी का चलेख करते हुए उप-संभावित (विन्य प्राणी एवं जीव विविधता संरक्षण) से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. ऊपरी मिट्टी एवं जोड़र बर्देन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
9. जल की आपूर्ति (शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन) स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रयुजिटेड इस्ट जर्जरेशन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर राघव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का संरक्षितता रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. ब्लास्टिंग का काम डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसकी विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अविधुयता का अा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लपित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/प्रस्तावों प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एसईएसी, भस्तीसगढ़ के अधिन दिनांक 30/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/04/2024 को जानकारी/प्रस्तावों प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024

समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रामाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप विन् गर वृक्षारोपण (पीपी) में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व में सीईआईएए. छ.ग. द्वारा डेनार्डिट (ग्रीन खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में डेनार्डिट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कहना है कि यह एक ग्रीन खनिज खदान है, ज़ुटियस मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-कोण्डागांव के अधिन क्रमांक 142/खनिज/2023-24 कोण्डागांव दिनांक 08/01/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 08/09/2017 से 31/03/2018 में विन् गये उत्खनन की मात्रा 345.582 घनमीटर है।
5. सीज बी विमल सुनिगा के नाम पर है। सीज सीज वर्ष 1983 से 2014 अवधि तक की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलधिकारी, कंकवाल वनमण्डल, कंकवाल, जिला-कोण्डागांव के अधिन क्रमांक 21/सा.वि./अन्त. 2023-24 वनमण्डल दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।

7. कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, फरसगढ़ उप वनमण्डल, वनमण्डल कैंसकाल, जिला-कोणार्गव के ज्ञापन क्रमांक 092 फरसगढ़, दिनांक 15/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र के निकलटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण से 200 कि.मी. की दूरी पर है।
8. ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वह पूर्व से संचालित ग्रेनाइट खान है। अतः पूर्व से ही ऊपरी मिट्टी उत्खनित की जा चुकी है, जिसका उपयोग लीज क्षेत्र के धारी और वृक्षारोपण में किया गया है। ओवर बर्डन का उपयोग सबकी के रख-रखाव हेतु किया जाता है।
9. रोज 3 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति नू-जल से की जाएगी। इस बाबत सेप्टम डायण्ड वीटर अपीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
10. एक्जिटिव डस्ट कन्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. पर्यवेक्षण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत वाउचर/पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. ब्लैस्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिभूत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पड़ोस राज्य वन और जलवायु परियोजना मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रदर्शन नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/06/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या फरसीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर.

एवं वृक्षांतर्पण का कार्य पूर्ण किये जाने की उपरांत गणित कि-वर्गीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सेष, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विक्रेता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विद्यार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के आपन क्रमांक 113/खनिज/2023-24 कोण्डागांव दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (घान-गड्डीपलना) का क्षेत्रफल 0.303 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. मेसर्स गड्डीपलना प्रेन्सईट माईन (प्री- वी लिमिटेड लुनिया) को घान-गड्डीपलना, तहसील-करसगांव, जिला-कोण्डागांव के खसरा क्रमांक 2/53 में स्थित प्रेन्सईट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.416 हेक्टेयर, समता - 1,764 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/08/2024 को संपन्न 181वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि समिति द्वारा प्रेन्सईट (मुख्य खनिज) खदान के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है, जबकि समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/06/2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 3 में "पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., घान, द्वारा प्रेन्सईट (मीन खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में प्रेन्सईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक मीन खनिज खदान है, बुनियादी मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।" का उल्लेख किया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आवेदित प्रकरण मुख्य खनिज या मीन खनिज का है? साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदित प्रकरण को मुख्य खनिज अथवा मीन खनिज, कौन से खनिज अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना है। उपरोक्त विवेकधियाँ के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विद्यार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिधेय में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एन.ई.ए.टी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के आपन क्रमांक 1232 दिनांक 20/11/2024 के माध्यम से एन.ई.ए.टी., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 08/10/2025

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त छात्रों के परिणाम में परीक्षण उपरान्त उपयुक्त अनुरोध किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.-३, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी.-३, छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद भाषण के साथ संपन्न हुई।


(श्री. सेंगासीमनी)

सदस्य सचिव,

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निरीक्षण

प्राधिकरण, छत्तीसगढ़


(पॉलिसेदटी वेकट नरसिंग राय)

अध्यक्ष,

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निरीक्षण

प्राधिकरण, छत्तीसगढ़


(श्री. बालेश कुमार जाधव)

सदस्य

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निरीक्षण

प्राधिकरण, छत्तीसगढ़